PRGI No. UPHIN/25/A1697

गरवी गुजरात

PUBLISHED HINDI DAILY FROM LUCKNOW

वर्ष : 02
अंक : 040
दि. 09.06.2026, मंगलवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

पीएम मोदी ने आर्मेनिया की सीसीपी पार्टी को दी बधाई, भारत के रक्षा उपकरणों का है बड़ा खरीदार

आर्मेनिया के संसदीय चुनाव में निकोल पेशिकयान की पार्टी की शानदार जीत पर पीएम मोदी ने बधाई दी। उन्होंने इसे जनता के अटूट विश्वास और मजबूत नेतृत्व की जीत बताया।

पीएम नरेंद्र मोदी ने आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पेशिकयान को संसदीय चुनाव में शानदार जीत पर बधाई दी

(जीएनएस)।

नई दिल्ली: पीएम नरेंद्र मोदी ने आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पेशिकयान को संसदीय चुनाव में उनकी पार्टी की शानदार जीत पर बधाई दी है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि यह जीत आर्मेनिया की जनता के उनके नेतृत्व और विजन पर गहरे विश्वास को दशार्ती है। प्रधानमंत्री मोदी के इस संदेश को भारत और आर्मेनिया के मजबूत होते संबंधों के लिहाज से अहम माना जा रहा है।

प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संदेश में कहा कि सिविल कॉन्ट्रैक्ट पार्टी (CPP) को मिला नया जनादेश आर्मेनिया के लोगों के भरोसे और विश्वास का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि चुनावी जीत केवल राजनीतिक सफलता नहीं है, बल्कि यह जनता की ओर से नेतृत्व को दिया गया मजबूत समर्थन भी है। मोदी ने पेशिकयान के नेतृत्व की सराहना करते हुए उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं।

संसदीय चुनावों में सिविल कॉन्ट्रैक्ट पार्टी की शानदार जीत पर निकोल पेशिकयान को हार्दिक बधाई। यह जनादेश आर्मेनिया की जनता के आपके नेतृत्व और विजन पर अटूट विश्वास का प्रतीक है। भारत और आर्मेनिया के बीच ऐतिहासिक मित्रता और सहयोग को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए मैं आपके साथ मिलकर काम करने को उत्सुक हूं।

भारत-आर्मेनिया संबंधों को नई मजबूती देने पर जोर

पीएम मोदी ने कहा कि वह निकोल पेशिकयान के साथ मिलकर भारत और आर्मेनिया के बीच ऐतिहासिक मित्रता और सहयोग के रिश्तों को और गहरा करने के लिए उत्सुक हैं। हाल के वर्षों में दोनों देशों के बीच रक्षा, व्यापार, टेक्नोलॉजी और रणनीतिक सहयोग के क्षेत्र में संबंध लगातार मजबूत हुए हैं।

क्षेत्रीय और वैश्विक सहयोग को मिलेगा बढ़ावा

विशेषज्ञों का मानना है कि पेशिकयान की जीत के बाद भारत और आर्मेनिया के बीच द्विपक्षीय सहयोग को नई गति मिल सकती है। दोनों देश

क्षेत्रीय स्थिरता, आर्थिक विकास और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने की दिशा में पहले से ही कई महत्वपूर्ण कदम उठा रहे हैं। पीएम मोदी का यह संदेश दोनों देशों के मजबूत और भरोसेमंद संबंधों का संकेत माना जा रहा है।

भारत के रक्षा उपकरणों का बड़ा खरीदार है आर्मेनिया

आर्मेनिया हाल के वर्षों में भारत के रक्षा उपकरणों का सबसे बड़ा विदेशी खरीदार बनकर उभरा है। दोनों देशों के बीच करीब 2 अरब डॉलर (लगभग 16 हजार करोड़ रुपये) की रक्षा साझेदारी विकसित हुई है।

अपनी सैन्य ताकत को आधुनिक बनाने के लिए आर्मेनिया बड़े पैमाने पर भारत में निर्मित हथियार और रक्षा प्रणालियां खरीद रहा है, जिससे दोनों देशों के रणनीतिक संबंध भी मजबूत हुए हैं।

आर्मेनिया ने भारत से आकाश मिसाइल प्रणाली, पिनाका मल्टी-बैरल रॉकेट लॉन्चर, 155 एमएम ATAGS तोपें, स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार, एंटी-टैंक मिसाइलें और ड्रोन-रोधी प्रणालियां खरीदी हैं।

विशेषज्ञों के मुताबिक भारतीय रक्षा उपकरणों की विश्वसनीयता, कम लागत और आधुनिक तकनीक ने आर्मेनिया को भारत का प्रमुख रक्षा साझेदार बनने के लिए प्रेरित किया है।

स्वच्छ भारत, पीएम आवास और डिजिटल इंडिया... पीएम मोदी ने सरकार के 12 साल पूरे होने पर गिनाए अच्छे काम

(जीएनएस)।

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को पिछले 12 वर्षों में अपनी सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कल्याणकारी उपायों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि भारत में कई बदलाव हुए हैं और इन इन बदलावों के मूल में गरीबों का कल्याण है।

अपने तीसरे कार्यकाल के दूसरे वर्ष के समापन पर पीएम मोदी ने प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, स्वच्छ भारत, पीएम आवास योजना और आयुष्मान भारत जैसी पहलों का उल्लेख करते हुए कहा कि इन सभी को लोगों को सम्मान और अवसर सुनिश्चित करने के एक सरल उद्देश्य से लाया गया है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार हमेशा अंत्योदय से प्रेरित रही है और उसका प्रयास हमेशा यह सुनिश्चित करना रहा है कि विकास के लाभ उन लोगों तक पहुंचें जो दशकों से पीछे छूट गए हैं।

पीएम ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि यह खुशी की बात है कि गरीबों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में प्रौद्योगिकी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

पीएम मोदी ने कहा कि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से सहायता सीधे और पारदर्शी तरीके से लोगों तक पहुंच रही है। इससे भ्रष्टाचार कम हुआ है, कार्यकुशलता बढ़ी है और शासन में विश्वास मजबूत हुआ है।

इसी तरह गरीब कल्याण को आगे बढ़ाने का सफर मानव सशक्तिकरण और विकसित भारत के हमारे सपने को साकार करने की दिशा में एक सामूहिक आंदोलन बन गया है।

केंद्र की कल्याणकारी योजनाओं से लोगों को वित्तीय सुरक्षा मिली: शाह

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास और जन-धन जैसी केंद्रीय योजनाओं ने करोड़ों नागरिकों को बैंकिंग सुविधाओं और वित्तीय सुरक्षा से जोड़ा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के तीसरे कार्यकाल के दूसरे वर्ष के समापन पर एक संदेश में शाह ने कहा कि गरीब कल्याण मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

अमित शाह ने कहा कि सरकार ने अन्न योजना, प्रधानमंत्री आवास, जन-धन, मुद्रा ऋण और प्रधानमंत्री स्वनिधि जैसी कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से करोड़ों नागरिकों को बैंकिंग सुविधाओं, वित्तीय सुरक्षा और स्वरोजगार के अवसरों से जोड़ा है।

टीएमसी में टूट? महुआ मोइत्रा ने बागियों को कहा 'गद्दार', यूसुफ पठान से पूछा- किसके इशारे पर दिल्ली जा रहे

(जीएनएस)।

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद तृणमूल कांग्रेस (TMC) के भीतर शुरू हुआ घमासान अब देश की राजधानी दिल्ली तक पहुंच गया है। पार्टी के संसदीय दल में एक बड़ी बगावत खड़ी हो गई है, जहां कई लोकसभा सांसद NDA सरकार के पाले में जाने की तैयारी कर रहे हैं।

इस राजनीतिक संकट और आंतरिक 'विस्फोट' के बीच TMC की फायरब्रांड नेता और कृष्णानगर से सांसद महुआ मोइत्रा अपनी पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी के समर्थन में मजबूती से खड़ी हो गई हैं। महुआ मोइत्रा ने एनडीए का रुख करने वाले बागी सांसदों पर तीखा हमला बोलते हुए उन्हें 'कायर और गद्दार' करार दिया है।

महुआ मोइत्रा ने रविवार शाम को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म '' पर बैक-टू-बैक कई पोस्ट शेयर कर बागियों को खुला चैलेंज दिया। उन्होंने लिखा- साल 2024 के लोकसभा चुनाव में इन सांसदों ने टीएमसी के टिकट पर जीत हासिल की थी। जनता ने इन्हें NDA के पक्ष में जनादेश नहीं दिया था। जितने भी लालची और खुदगर्ज गद्दार अपनी पैंट पीली कर (डरकर) अब बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं, वे कृपया तुरंत अपनी सीट से इस्तीफा दें और बीजेपी के टिकट पर दोबारा चुनाव लड़कर दिखाएं। देखते हैं कि वे कितने बड़े सूरमा हैं।

महुआ मोइत्रा ने अपने हमले के दायरे में बहरामपुर से TMC सांसद और टीम इंडिया के पूर्व स्टार क्रिकेटर यूसुफ पठान को भी ले लिया। हालांकि, अभी यह पूरी तरह साफ

नहीं है कि यूसुफ पठान बागी गुट के साथ हैं या नहीं, लेकिन महुआ ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बहाने उन पर तीखा तंज कसा। महुआ ने लिखा, यूसुफ पठान, क्या आप अमित शाह के बुलावे पर इतनी जल्दी दिल्ली भाग रहे हैं? थोड़ी हिम्मत दिखाइए। आप भारत के लिए खेले हैं। हमारे जिले की जनता ने आपको भारी मतों से जिताकर संसद भेजा है। थोड़ी शर्म रखिए और रीढ़ की हड्डी सीधी रखिए।

पिछले दिनों राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा जोरों पर थी कि सौरव गांगुली ने ममता बनर्जी और यूसुफ पठान के बीच मध्यस्थता की थी। रिपोर्टों में दावा किया गया था कि ममता चाहती थीं कि यूसुफ सांसद पद से इस्तीफा दे दें, ताकि एक उपचुनाव के जरिए पूर्व मुख्यमंत्री (ममता बनर्जी) खुद लोकसभा में प्रवेश कर सकें। हालांकि, सौरव गांगुली ने इन खबरों को सिरे से खारिज करते हुए किसी भी तरह की मध्यस्थता से इनकार किया है।

यह विवाद तब और गहरा गया जब बागी टीएमसी सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने समाचार एजेंसी 'ANI' से कहा- TMC के लगभग 20 लोकसभा सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर NDA सरकार को समर्थन देने की पेशकश की है।

क्या कहती है कानूनी स्थिति?

साल 1998 में ममता बनर्जी द्वारा गठित की गई टीएमसी के इस समय लोकसभा में कुल 28 सदस्य हैं। संविधान के दलबदल विरोधी कानून (अल्ल३-ऊीृ३ङ्गल्ल छं६) के तहत, अपनी सदस्यता गंवाए बिना पार्टी से अलग होने या नया गुट बनाने के लिए किसी भी धड़े को कम से कम दो-तिहाई (2/3) सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है। टीएमसी लोकसभा गणित (कुल सांसद: 28)

दलबदल से बचने के लिए जरूरी संख्या: 19 सांसद

बागी गुट का दावा: 20 सांसद

यदि बागी गुट का 20 सांसदों का दावा सच साबित होता है, तो वे कानूनी रूप से अयोग्य होने से बच जाएंगे। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के लिए यह दूसरा बड़ा झटका है। इससे पहले राज्य विधानसभा में निष्कासित विधायक रीताब्रत बनर्जी ने कम से कम 58 विधायकों के साथ एक अलग गुट बनाकर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष (LoP) का पद हासिल कर लिया था। यह पूरी उथल-पुथल राज्य में हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों में टीएमसी की करारी हार के बाद शुरू हुई है, जिसके बाद शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बंगाल में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी है।

इंडिया गठबंधन की बैठक पर गिरिराज सिंह का बड़ा बयान, 'कांग्रेस अकेले प्रधानमंत्री मोदी से. . .

(जीएनएस)।

पटना, दिल्ली में सोमवार (08 जून, 2026) को हुई इंडिया गठबंधन की बैठक पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा बयान आया है. गिरिराज सिंह ने इस बैठक को लेकर विपक्षी दलों पर हमला बोला है. उन्होंने प्रधानमंत्री का नाम लेते हुए कांग्रेस को चुनौती भी दी है.

गिरिराज सिंह ने कहा, "मल्लिकार्जुन खरगे क्या कहेंगे, 25 नहीं वे 50 दलों को मिला लें, ये लोग वंशवाद के पोषक हैं. खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष, बेटा उपमुख्यमंत्री, राहुल गांधी राष्ट्रीय नेता, गांधी परिवार से निकलेंगे नहीं... कांग्रेस अकेले प्रधानमंत्री मोदी से मुकाबला नहीं कर सकती..."

आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के एक बयान पर उन्होंने कहा, "वे ऐसे ही बूथ कैप्चर करना चाहते हैं जैसे उनके पिताजी करते थे? वह जमाना

अब गया. ये लोग वंशवादी हैं, सत्ता के बिना रह नहीं सकते इसलिए मुंगेरीलाल के हसीन सपने देख रहे हैं."

गिरिराज सिंह ने 20 ळटउ सांसदों के बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को समर्थन देने की खबरों पर कहा, "ये सांसद और विधायक भी अपना भविष्य देख रहे होंगेङ्घ जनता हिसाब लेना चाहती है. टीएमसी अब खत्म हो चुकी है. टीएमसी का नामों-निशान नहीं है, इसलिए डूबती जहाज पर कौन बैठेगा?"

बता दें कि दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आज (08 जून) इंडिया ब्लॉक की बैठक हुई है. इस बैठक में सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी सहित 25 दलों के नेता शामिल हुए. बैठक के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई. इसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने बताया कि बैठक में शामिल सभी दलों में पांच मुद्दों पर सहमति बनी है.

मेरठ मॉडल ने आरोप लगाया है कि उसे एक दशक से शोषण और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव का सामना करना पड़ा है।

पुलिस की सोमवार की रिपोर्ट के अनुसार, मेरठ की एक मॉडल ने शादी का बहाना बनाकर लगभग एक दशक तक शारीरिक और आर्थिक रूप से उसका शोषण करने और बाद में उसे धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया है। सरधना क्षेत्र की रहने वाली इस महिला ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। मेरठ की महिला ने दीर्घकालिक शोषण का दावा किया, अपनी शिकायत में, महिला ने बताया कि उसकी मुलाकात 2015-16 में मुंबई में एक मॉडलिंग ट्रिप के दौरान आरोपी से हुई थी, जो सरधना का ही रहने वाला है। उसने आरोप लगाया कि उसने उसके करियर में मदद करने और अंततः उससे शादी करने का वादा किया था।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने दिल्ली में यमुना पुनजीर्वीकरण के मुद्दे पर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की

(जीएनएस)।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने दिल्ली में यमुना पुनजीर्वीकरण के मुद्दे पर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में केन्द्रीय आवासन एवं शहरी विकास मंत्री श्री मनोहर लाल, केन्द्रीय जलशक्ति मंत्री श्री सी आर पाटिल, दिल्ली के उप-राज्यपाल श्री तरणजीत सिंह संधु, मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता, श्री प्रवेश साहिब सिंह सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

बैठक में केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि साफ और स्वच्छ यमुना प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा संकल्प है और हम सभी को मिलकर इससे जल्दी ही पूरा करना है। उन्होंने कहा कि दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकारें व सभी संबंधित मंत्रालय, यमुना की स्वच्छता के लिए टुकड़ों में नहीं बल्कि एक टीम भावना से एकीकृत कार्य योजना के तहत काम करें।

श्री अमित शाह ने कहा कि हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश तीनों राज्य मिलकर यमुना नदी में मानक ईको-फ्लो सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि दिल्ली की डेयरियों के wastage को यमुना में जाने से रोकने के लिए दिल्ली नगर निगम (MCD) और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) के बीच टङ्कव साइन होगा, जो इसे गोबर गैस तथा खाद में तब्दील करेगा। गृह मंत्री ने यह भी कहा कि NDDB मॉडल के तहत डेयरी और गौशालाओं का गोबर सीधे गैस और खाद प्लांट तक पहुंचेगा और साथ ही यमुना किनारे के कचरे का वैज्ञानिक प्रबंधन होगा।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि यमुना नदी में प्रवाहित नालों की डीसिल्टिंग का काम तेजी से चल रहा है। इस वर्ष लक्षित 28.57 लाख MT में से 97% गाद निकाली जा चुकी है और बाकी 15 जून तक निकाल ली जाएगी। उन्होंने निर्देश दिया कि गाद का इस्तेमाल विभिन्न विनिर्माण परियोजनाओं में किया जाए, जिससे बारिश में ये गाद बहकर वापस यमुना में न जाये।

श्री अमित शाह ने कहा कि दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में अब तक 129 STP बन चुके हैं और 2027 के अंत तक 59 नए STP's और बनाये जाएँगे। गृह मंत्री ने निर्देश दिए कि STPs, औद्योगिक wastage और सभी नालों के डिस्चार्ज को अच्छे से मॉनिटर करें। उन्होंने कहा कि सिर्फ संतोषजनक काम नहीं बल्कि सटीक परिणाम आने चाहिए। श्री शाह ने यह भी कहा कि औद्योगिक CETP या डेयरी वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट्स- सभी का निर्माण भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ही हो।

टूट गया इंडिया गंठबंधन? कांग्रेस की बैठक से डीएमके की दूरी पर उठे सवाल, अब पार्टी ने क्या कहा

(जीएनएस)।

दिल्ली में सोमवार, 8 जून 2026 को आयोजित 'INDIA' गठबंधन की बैठक के बीच विपक्षी खेमे से एक बड़ी खटपट देखने को मिली है। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) ने का बैठक में शामिल नहीं होने पर इंडिया ब्लॉक में टूट के संकेत नजर आ रहे थे लेकिन अब DMK ने अपने रुख को लेकर बड़ा बयान दिया है।

कांग्रेस की अगुवाई में आयोजित बैठक में शामिल न होने को लेकर उठ रहे सवालों के बीच ऊटङ ने स्पष्ट किया कि बैठक में भाग नहीं लेने का मतलब यह नहीं है कि पार्टी INDIA गठबंधन से दूर हो रही है। पार्टी ने कहा कि वह गठबंधन की मूल विचारधारा और उसके प्रमुख मुद्दों के साथ खड़ी है।

DMK के वरिष्ठ नेता और पार्टी प्रवक्ता टीकेएस एलंगोवन ने सोमवार को कहा कि उनकी पार्टी ने पहले ही अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी थी और कांग्रेस के नेतृत्व वाले इस विशेष गठबंधन मंच की बैठक में शामिल न होने का फैसला लिया था। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि जिन मुद्दों और प्रस्तावों पर चर्चा हुई है, उनमें से अधिकांश DMK की वैचारिक सोच से मेल खाते हैं।

चेन्नई में मीडिया से बात करते हुए डीएमके प्रवक्ता टीकेएस एलंगोवन ने गठबंधन की बैठक में शामिल न होने के फैसले पर पार्टी का स्टैंड साफ किया। उन्होंने सीधे शब्दों में कहा- हमने अपनी स्थिति पूरी तरह स्पष्ट कर दी है। हम कांग्रेस के नेतृत्व वाले इस गठबंधन में हिस्सा नहीं लेने जा रहे हैं। हमारे कार्यकताओं की भावनाएं आहत हुई हैं और पार्टी नेतृत्व ने फैसला किया है कि हम उस बैठक से दूर रहेंगे जिसमें कांग्रेस शामिल हो रही है।

गौरतलब है कि तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के बाद दोनों दलों के बीच दरार आ गई थी, जब कांग्रेस ने डीएमके का साथ छोड़कर अभिनेता से नेता बने सी. जोसेफ विजय की पार्टी 'तमिलगा वेत्री कड़गम' (TVK) के नेतृत्व वाली सरकार को समर्थन देने का फैसला किया था। डीएमके इसे कांग्रेस द्वारा किया गया विश्वासघात मान रही है।

सम्पादकीय

शांति नहीं युद्ध, कुछ और ही कहानी की ओर इशारा कर रही होर्मूज क्षेत्र में चल रही तैयारियां

नाम पर धोखा? क्या अमेरिका ईंरान पर जमीनी हमले की तैयारी कर रहा है और सीजफायर के नाम पर ईंरान को बेववूफ बना रहा है? अमेरिकी वारशिप यूएसएस त्रिपोली की तैनाती के बाद सवाल फिर यह उठ गया है कि अमेरिका की असल नीयत क्या है? त्रिपोली की तैनाती के बाद यह सवाल उठाना लाजमी है। अमेरिकी सेना ने शनिवार को ईंरान की ओर से लांच किए गए ड्रोन को तबाह कर देने का दावा किया। वहीं अब होर्मूज में यूएसएस त्रिपोली की तैनाती की ताजा खबर आई है। सवाल उठता है कि क्या ईंरान पर अब जमीनी हमला होने जा रहा है? अमेरिका और ईंरान के बीच शांति वार्ता कहने को तो अभी जारी है। लेकिन जमीन और समुद्र पर जो स्थिति दिख रही है वे वुछ और ही कहानी की ओर इशारा कर रही है। पिछले 72 घंटों में हुईं कईं सैन्य कार्रवाईंयों ने पश्चिम एशिया में नए सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अमेरिका सिर्प ईंरान पर दबाव बना रहा है या फिर होर्मूज जलडमरूमध्य पर निर्णायक बढ़त हासिल करने की तैयारी कर रहा है? क्योंकि जो तैनाती अमेरिका कर रहा है, उसे देखकर तो ऐसा लगता है कि ट्रंप अब ईंरान के आइलैंड पर कब्जा करने जा रहा है? घटनाओं की शुरूआत उस खबर से हुईं जिसमें बताया गया कि ईंरानी झंडे वाले चार तेल टैंकर होर्मूज पार करने में सफल रहे। ये जहाज कथित तौर पर करीब 70 लाख बैरल तेल लेकर निकले थे और प्रतिबंधों के बावजूद आगे बढ़ गए। लेकिन इसके वुछ ही घंटों बाद अमेरिकी इंडो-पैसेफिक कमांड ने घोषणा की कि उसने हिंद महासागर में प्रतिबंधित तेल टैंकर एमटी डेविना को रोककर इस पर कब्जा कर लिया है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि कब्जे में लिया गया जहाज उन्हीं चार टैंकरों में से एक था या नहीं। लेकिन टाइमिंग ने कईं अटकलों को जन्म दिया है। इसे मसले पर संभल ही रहा था कि उस पर अमेरिका ने हमला कर दिया। शनिवार को ही अमेरिकी सैंट्रल कमांड ने दावा किया कि उसने होर्मूज की ओर बढ़ रहे चार ईंरानी हमलावर ड्रोन मार गिराए। इसके तुरंत बाद अमेरिकी सेना ने ईंरान के गोसक और केशम द्वीप पर मौजूद तटीय रडार ठिकानों पर हमले किए। पहली बार नहीं है जब केशम को निशाना बनाया गया है। लेकिन मौजूदा हालात में इस द्वीप का नाम बार-बार सामने आना सैन्य विश्लेषकों का ध्यान खींच रहा है। जवाब में ईंरान ने भी वुवैत और बहरीन की ओर सात मिसाइलें दागी। इनमें से 6 को अमेरिका ने रोकने का दावा किया। इस बीच अमेरिका ने यूएसएस त्रिपोली की अरब सागर और होर्मूज क्षेत्र में तैनाती की है। यूएसएस त्रिपोली कोईं साधारण युद्ध पोत नहीं है। यह एक उभयचर हमलावर जहाज है, जिसका मतलब है कि ये जहाज पानी से तो हमला कर ही सकता है, जरूरत पड़ने पर जमीन के बेहद करीब जाकर सैनिकों को उतार भी सकता है। ऐसे जहाज समुद्र से सीधे सैन्य अभियान चलाए जाने के लिए बनाए जाते हैं। उधर केशम ईंरान का सबसे बड़ा द्वीप है और होर्मूज के मुहाने पर मौजूद है। इसे न डूबने वाला एयरव्राफ्ट कैरियर भी कहा जाता है। ईंरान ने यहां वर्षो से रडार सिस्टम, ड्रोन बेस, एंटी शिप मिसाइलें, अंडरग्राउंड सुरंगे और नौ सैनिक अड्डे बनाए हुए हैं। अगर अमेरिका इस द्वीप पर कब्जा कर लेता है तो उसे कईं बड़े स्ट्रेटिजिक फायदे मिल सकते हैं। वैसे अमेरिका के लिए केशम पर कब्जा बिल्वुल भी आसान नहीं होने वाला है। इसका मतलब होगा सीधे अंगारों को हाथ में लेना। केशम ईंरानी जमीन से बेहद करीब है। अगर अमेरिका अपने सैनिकों को यहां उतारता है तो उसे ईंरान की मिसाइलों, ड्रोन, नौ सैनिक हमलों और संभावित गुरिल्ला प्रतिरोध का सामना करना पड़ सकता है। यूएसएस त्रिपोली की मौजूदगी, केशम पर लगातार हमले और टैंकरों को रोकने जैसी कार्रवाईंयों ने यह बहस तेज कर दी है कि अमेरिका होर्मूज पर रणनीतिक बढ़त लेने की कोशिश कर रहा है।

विदेशी संसदों में सबसे ज्यादा संबोधन देने वाले भारतीय प्रधानमंत्री बन चुके हैं पीएम मोदी.

10 जून 2026 को भारत की सियासत में पीएम मोदी सलगातार सबसे लंबे समय तक पीएम रहने वाले नेता बनेंगे. नेहरू ने जब अमेरिकी संसद में अपना भाषण दिया था. तब भारत अपनी आजादी बचाने की लड़ाई लड़ रहा था. नेहरू ने अमेरिका से कोई फायदा नहीं मांगा. पीएम मोदी ने ग्लोबल लेवल पर 2014 से 2026 के बीच 19 विदेशी संसद में भाषण दिया है.

(जीएनएस)।

नई दिल्ली. जब कोई प्रधानमंत्री किसी विदेशी संसद में भाषण देता है, तो उस पल का महत्व प्रोटोकॉल से कहीं ज्यादा होता है. इसका मतलब है कि दूसरा देश न सिर्फ. भारत के नेता की मेजबानी कर रहा है, बल्कि अपनी लोकतांत्रिक संसद में झ कानून बनाने वालों, राजनयिकों, मीडिया और पूरी दुनिया के सामने झ भारत की आवाज को जगह भी दे रहा है. यहीं पर नेहरू और पीएम मोदी के बीच का अंतर अहम हो जाता है. जवाहरलाल नेहरू ने अपने कार्यकाल के दौरान तीन विदेशी संसदों को संबोधित किया था. वहीं, पीएम नरेंद्र मोदी ने 2014 से 2026 के बीच 19 विदेशी संसदों को संबोधित किया है, जो किसी भी भारतीय कार्यकारी प्रमुख के लिए सबसे ज्यादा है.

जैसे-जैसे पीएम मोदी 10 जून, 2026 को भारत के सबसे लंबे समय तक लोकतांत्रिक रूप से चुने गए और लगातार सेवा करने वाले प्रधानमंत्री के तौर पर नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ने के करीब पहुंच रहे हैं, ये भाषण दिखाते हैं कि कैसे भारत की ग्लोबल आवाज पहचान की शुरूआती कोशिशों से आगे बढ़कर दुनिया की राजधानियों में एक व्यापक और ज्यादा आत्मविश्वास भरी मौजूदगी तक पहुंची है.

अमेरिकी सांसदों को नेहरू का 1949 का संबोधन तब हुआ था जब भारत-अमेरिका संबंध अभी शुरूआती दौर में थे. हाउस चैंबर की मरम्मत चल रही थी, इसलिए उन्होंने सीनेट जाने से पहले 'वेज एंड मीन्स कमेटी रूम' में एक स्वागत समारोह में लगभग 15 मिनट तक भाषण दिया; सीनेट की बैठक उस समय पुराने सुप्रीम कोर्ट चैंबर में हो रही थी, जहां उन्होंने वही भाषण फिर से दिया. उस समय, राष्ट्रपति हैरी एस. ट्रूमैन का वॉशिंगटन नेहरू की गुटनिरपेक्षता और समाजवादी सोच को समझने की कोशिश कर रहा था. वहीं भारत, शीत युद्ध के गुटों में तेजी से बँट रही दुनिया में अपनी नई-नई मिली आजादी की रक्षा करने की कोशिश कर रहा था.

नेहरू का संदेश सावधानी भरा लेकिन स्पष्ट था. उन्होंने कहा कि वह अमेरिका के 'दिमाग और दिल' को 'जानने-समझने की यात्रा' पर आए हैं और उसके सामने भारत का अपना 'दिमाग और दिल' रखना चाहते हैं. उन्होंने तकनीकी और यांत्रिक सहयोग का स्वागत किया, लेकिन इस बात पर जोर दिया कि भारत सबसे पहले आत्मनिर्भरता पर भरोसा करेगा और अपनी 'मुश्किल से हासिल की गई आजादी' के किसी भी हिस्से के बदले 'कोई भौतिक फायदा' नहीं चाहेगा. यह एक ऐसे नए आजाद देश की आवाज थी जो बिना निर्भरता के सहयोग चाहता था.

विदेशों की संसदों में पीएम मोदी का संबोधन भारत की वैश्विक यात्रा के एक अलग दौर का हिस्सा है. उनके भाषणों ने भारत का संदेश पड़ोसी देशों, प्रमुख पश्चिमी लोकतंत्रों, अफ्रीका, कैरिबियन, इंडो-पैसिफिक और पश्चिम एशिया की संसदों तक पहुंचाया है. 2014 में पद संभालने के तुरंत बाद, मोदी ने भूटान, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया और फि जी की संसदों को संबोधित किया. 2015 में, उन्होंने मॉरीशस की नेशनल असेंबली, श्रीलंका की संसद, मंगोलिया की संसद, यूके की संसद और अफगानिस्तान की संसद को संबोधित किया. उन्होंने 2016 और फिर 2023 में अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित किया. बाद की सूची और भी बढ़ीः 2018 में युगांडा, 2019 में मालदीव, 2024 में गुयाना, 2025 में घाना, त्रिनिदाद और टोबैगो, नामीबिया और इथियोपिया, और 2026 में इजरायल की नेसेट (संसद). नेसेट में, जो उनका हालिया संबोधन था, पीएम मोदी को इजरायली संसद के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया.

अमेरिकी कांग्रेस में पीएम मोदी ने क्या कहा

पीएम मोदी का 2016 का संबोधन नेहरू के 1949 के भाषण से बिल्कुल अलग स्थिति में हुआ था. तब तक, राष्ट्रपति बराक ओबामा के कार्यकाल में भारत-अमेरिका संबंध एक मजबूत रणनीतिक दौर में पहुंच चुके थे; ओबामा अपने कार्यकाल के दौरान दो बार भारत का दौरा करने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बने थे. व्यापार 2009 में $60 बिलियन से बढ़कर 2015 में $107 बिलियन हो गया था, अमेरिका से भारत की रक्षा खरीद $14 बिलियन तक पहुंच गई थी, और अमेरिका में भारतीय ऋक्कतीन गुना हो गया था. वह आत्मविश्वास पीएम मोदी की भाषा में झलकता था. अटल बिहारी वाजपेयी के 'हिचकिचाहट की छाया' से बाहर निकलने के आ'ान का ज़िक्र करते हुए, मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका ने 'इतिहास की हिचकिचाहटों' को पार कर लिया है. उन्होंने संबंधों को परिभाषित करने के लिए 'सहजता, स्पष्टता और तालमेल' जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया और कहा कि अमेरिकी कांग्रेस ने 'बाधाओं को साझेदारी के पुलों में बदलने' में मदद की है.

2023 में, पीएम मोदी अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को दो बार संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने. इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बाद, वे ऐसे दूसरे अंतरराष्ट्रीय नेता भी हैं जिन्हें एक से ज्यादा बार यह सम्मान मिला है. उनके 2023 के भाषण से पता चला कि दुनिया में भारत की स्थिति कितनी बदल गई है. पीएम मोदी ने कहा कि जब वह पहली बार प्रधानमंत्री के तौर पर अमेरिका गए थे, तब भारत दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था, और अब यह पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है. उन्होंने कहा, 'जब भारत आगे बढ़ता है, तो पूरी दुनिया आगे बढ़ती है.' पीएम मोदी ने 'वसुधैव कुटुंबकम' झ यानी दुनिया एक परिवार है झ के विचार के जरिए दुनिया के साथ भारत के जुड़ाव को भी पेश किया. इसे भारत की ऋ20 थीम 'एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य' से जोड़ते हुए उन्होंने कहा कि दुनिया के साथ भारत का जुड़ाव सभी के फायदे के लिए है.

दूसरे देशों की संसद में भाषण क्यों मायने रखते हैं

दूसरे देशों की संसद में दिए गए भाषण प्रतीकात्मक होते हैं, लेकिन कूटनीति में प्रतीकों का महत्व होता है. ऐसे निमंत्रण तब दिए जाते हैं जब कोई देश सम्मान दिखाना चाहता है, राजनीतिक संबंध मजबूत करना चाहता है या आने वाले नेता के महत्व को मान्यता देना चाहता है. इसीलिए पीएम मोदी के 19 भाषण मायने रखते हैं. ये न सिर्फ. व्यक्तिगत कूटनीति को दिखाते हैं, बल्कि एक ऐसे देश के तौर पर भारत की व्यापक स्वीकार्यता को भी दशार्ते हैं जिसकी स्थिति अलग-अलग क्षेत्रों और मुद्दों पर अहम है.

'कॉकरोच जनता पार्टी बीजेपी की ' सी टीम' है', कह रहे सस्पेंडेड पीसीएस अधिकारी? कार्यक्रमों को मिली अनुमति का हवाला देते हुए सरकार की मंशा पर सवाल उठाए

(जीएनएस)।

सस्पेंडेड बरेली सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने एक बार फिर ऐसा विवादित बयान दिया है, जिसके बाद एक बार फिर वो सुर्खियों में हैं। बलरामपुर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान 'कॉकरोच जनता पार्टी (CJP)' को भाजपा की 'सी टीम' बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता और विपक्ष के बीच दिखने वाला टकराव कई मामलों में सिर्फ दिखावा है।

अग्निहोत्री ने दावा किया कि जिस संगठन को सार्वजनिक मंचों पर राष्ट्रविरोधी बताया जाता है, उसके नेताओं को कई मौकों पर प्रशासनिक और राजनीतिक संरक्षण मिलता दिखाई देता है। उन्होंने CJP नेता अभिजीत दीपके के स्वागत और उनके कार्यक्रमों को मिली अनुमति का हवाला देते हुए सरकार की मंशा पर सवाल उठाए।

अपने संबोधन में उन्होंने राम मंदिर में आने वाली दान राशि को लेकर भी गंभीर चिंता जताई। आरोप लगाया कि श्रद्धालुओं द्वारा दिए गए करोड़ों रुपये के चंदे के उपयोग को लेकर पारदर्शिता जरूरी है और धार्मिक संस्थाओं की संपत्ति के प्रबंधन पर सार्वजनिक जवाबदेही सुनिश्चित होनी चाहिए। उन्होंने कहा आस्था से जुड़े मुद्दों को राजनीति और आर्थिक हितों से अलग रखा जाना चाहिए।

हालांकि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से कहा गया है कि

दान राशि और वित्तीय लेन-देन की आंतरिक ऑडिट प्रक्रिया जारी है तथा अब तक किसी ठोस अनियमितता की पुष्टि नहीं हुई है।

पुलिस एनकाउंटर पर भी उठाए सवाल

अग्निहोत्री ने अपने भाषण में पुलिस एनकाउंटर नीति और प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कानून के शासन में हर कार्रवाई निर्धारित प्रक्रिया के तहत होनी चाहिए और किसी भी प्रकार के अधिकारों के दुरुपयोग से बचना जरूरी है।

कौन हैं अलंकार अग्निहोत्री?

अलंकार अग्निहोत्री मूल रूप से कानपुर के मूल निवासी हैं। उन्होंने यूपीपीएससी 2016 परीक्षा में 15वीं रैंक हासिल की थी इसके बाद 2019 बैच के पीसीएस अधिकारी के रूप में सलेक्ट हुए थे।

अलंकार अग्निहोत्री इंजीनियरिंग स्नातक (B.Tech) हैं और उन्होंने कानून (LLB) की भी पढ़ाई की है। उनकी शिक्षा और चयन प्रक्रिया को लेकर उन्हें शुरूआती करियर में एक मेधावी अधिकारी के रूप में देखा जाता रहा है। इन्होंने विभिन्न जिलों में एसडीएम और डिप्टी कलेक्टर के रूप में कार्य किया, लखनऊ में सहायक नगर आयुक्त के पद पर भी रहे और बाद में बरेली सिटी मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात रहे हैं।

क्यों हुए थे सस्पेंड?

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 26 जनवरी 2025 को अलंकार अग्निहोत्री को निलंबित कर दिया था। उन्होंने सर्वाजनिक मंच से यूजीसी के नए नियमों पर सवाल उठाते कहा था कि वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। जिसके बाद अनुशासनहीनता और सेवा आचरण नियमों के उल्लंघन के आरोप लगाते ही दूसरे ही दिन सस्पेंड कर दिया गया था।

निलंबन के बाद उन्हें जांच पूरी होने तक शामली जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय से संबद्ध (अटैच) किया गया था। याद रहे सरकारी सेवा नियमों के तहत किसी भी अधिकारी को राजनीतिक या विवादास्पद सार्वजनिक गतिविधियों में भाग लेने से पहले निर्धारित नियमों का पालन करना होता है।

शंकराचार्य स्वामी के माघ मेले में की व्यवस्था पर जताई थी आपत्ति

प्रयागराज माघ मेले के दौरान शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से जुड़े एक मामले में उन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था पर आपत्ति जताई थी। उनका कहना था कि कुछ घटनाएं धार्मिक परंपराओं और सामाजिक सम्मान के खिलाफ हैं, जिस पर उन्होंने सार्वजनिक रूप से विरोध दर्ज कराया था।

कब और कहां होगा भारत-अफगानिस्तान के बीच पहला वनडे? क्या है टॉस का टाइम

(जीएनएस)।

भारतीय क्रिकेट टीम ने अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट मैच में एक पारी और 300 रनों से ऐतिहासिक जीत दर्ज करके सीरीज अपने नाम कर ली है। टेस्ट प्रारूप में अफगान टीम को चारों खाने चित करने के बाद अब दोनों टीमों के बीच सीमित ओवरों की जंग शुरू होने वाली है। क्रिकेट फैंस अब दोनों देशों के बीच होने वाली रोमांचक एकदिवसीय सीरीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

टेस्ट मैच की कड़वी यादों को भुलाकर अफगानिस्तान की टीम वनडे सीरीज में नए इरादों के साथ वापसी करने के लिए पूरी तरह बेताब नजर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ शानदार फॉर्म में चल रही भारतीय टीम अपनी इस बादशाहत को वनडे फॉर्मेट में भी बरकरार रखना चाहेगी। दोनों टीमों के बीच होने वाले इस पहले मुकाबले को लेकर शेड्यूल और वेन्यू की सभी आधिकारिक जानकारियां सामने आ चुकी हैं।

क्रिकेट फैंस के लिए अच्छी खबर यह है कि भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की इस वनडे सीरीज का पहला मुकाबला शनिवार 13 जून 2026 को खेला जाएगा। वीकेंड के दिन होने वाले इस मुकाबले को लेकर दर्शकों में अभी से भारी उत्साह देखा जा रहा है। इस मुकाबले में दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर होने की पूरी उम्मीद है।

यह हाई-वोल्टेज मुकाबला हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम धर्मशाला के बेहद खूबसूरत मैदान पर खेला जाएगा। धर्मशाला की तेज पिचों पर तेज गेंदबाजों को हमेशा शुरूआती मदद मिलती है, जिससे मैच और भी ज्यादा रोमांचक होने की उम्मीद है। बफीली पहाड़ियों के बीच बने इस खूबसूरत स्टेडियम में फैंस को एक बेहतरीन मुकाबला देखने को मिलेगा।

समय की बात करें तो भारत और अफगानिस्तान का यह पहला वनडे मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। मैच शुरू होने से ठीक आधा घंटा पहले यानी दोपहर 1:00 बजे दोनों कप्तानों के बीच टॉस उछाला जाएगा।

विराट कोहली हो चुके हैं बाहर

टीम इंडिया के स्टार खिलाड़ी विराट कोहली इस सीरीज से बाहर हो गए हैं। आईपीएल के फाइनल के दौरान ही उनको चोट लगी थी। हेमस्ट्रिंग में प्रॉब्लम की वजह से कोहली नहीं खेल रहे हैं। उनकी जगह ऋतुराज गायकवाड़ को टीम में शामिल किया गया है।

क्रिस्टन वेल्कर कौन हैं, जिसे ट्रंप ने बीच इंटरव्यू बेईमान-मूर्ख कहा? तीखी बहस में माइक फेंककर चले गए

(जीएनएस)।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एनबीसी न्यूज के लोकप्रिय शो 'मीट द प्रेस' की मॉडरेटर क्रिस्टन वेल्कर के साथ एक हाई-प्रोफाइल इंटरव्यू के दौरान तीखी बहस हुई। इसके बाद, ट्रंप ने माइक्रोफोन फेंककर इंटरव्यू बीच में ही छोड़

दिया। ट्रंप ने वेल्कर को 'बेईमान' और 'मूर्ख' बताते हुए एनबीसी को 'एकतरफा और भ्रष्ट नेटवर्क' करार दिया। यह घटना रविवार (7 जून) को प्रसारित हुई, जो ट्रंप के मीडिया के साथ तनावपूर्ण संबंधों का नया उदाहरण बन गई है।

यह इंटरव्यू विस्कॉन्सिन में बारिश की चुनौती भरी परिस्थितियों के बीच टेप किया गया था। जब वेल्कर ने 2020 के चुनाव में कथित धांधली और हालिया कैलिफोर्निया प्राइमरी में वोट गिनती की देरी पर सबूत मांगे, तो ट्रंप उत्तेजित हो गए और इंटरव्यू खत्म कर दिया। आइए विस्तार से समझें क्या-क्या हुआ?

क्रिस्टन वेल्कर अमेरिकी टेलीविजन पत्रकारिता की प्रमुख हस्तियों में से एक हैं। उनका जन्म 1 जुलाई 1976 को फिलाडेल्फिया, पेंसिल्वेनिया में हुआ। वे एनबीसी न्यूज की व्हाइट हाउस संवाददाता रह चुकी हैं और सितंबर 2023 से मीट द प्रेस का संचालन कर रही हैं। वे इस शो की 13वीं मॉडरेटर और पहली अश्वेत महिला हैं, जिन्होंने इस ऐतिहासिक कार्यक्रम की कमान संभाली।

वेल्कर ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से अमेरिकी इतिहास में स्नातक (कम लॉड) किया। करियर की शुरूआत कैलिफोर्निया के रेडिंग में लोकल न्यूज एंकर, कैमरा ऑपरेटर और मौसम रिपोर्टर के रूप में हुई। 2005 में फिलाडेल्फिया के एनबीसी सहयोगी स्टेशन में रिपोर्टर बनीं। 2011 में वे एनबीसी न्यूज की व्हाइट हाउस टीम में शामिल हुईं और बाद में चीफ व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट बनीं।

2020 में उन्होंने पीटर अलेक्जेंडर के साथ वीकेंड टुडे को-एंकर किया। 2020 के राष्ट्रपति चुनावी डिबेट की मॉडरेटर के रूप में भी वे चर्चा में रहीं। उनकी रिपोर्टिंग ठइउ ढ्रॅ३'८ ठीद२, ळ्ङ्ग्िट शो और टरठइउ पर नियमित रूप से दिखती है।

परिवार में कौन-कौन है?

वे 2017 से जॉन 'ज़ेस से शादीशुदा हैं। दंपति की दो संतानें हैं। वेल्कर को उनकी संतुलित, कठोर लेकिन सम्मानजनक पूछताछ शैली के लिए जाना जाता है। मीट द प्रेस अमेरिका का सबसे पुराना टेलीविजन कार्यक्रम है, जो 1947 से चल रहा है। वेल्कर ने चक टॉड की जगह ली और इसे नई ऊर्जा दी।

क्या हुआ इंटरव्यू में?

इंटरव्यू शुक्रवार (5 जून) को विस्कॉन्सिन के एक फार्महाउस (बार्न) में टेप किया गया, जहां भारी बारिश की वजह से आवाज में दिक्कत हो रही थी। विषयों में ईरान युद्ध, अर्थव्यवस्था, 'एंटी-वेपनाइजेशन' फंड (6 जनवरी कैपिटल दंगे से जुड़े लोगों के लिए प्रस्तावित फंड) और चुनावी मुद्दे शामिल थे।

जब बात कैलिफोर्निया की जून 2026 प्राइमरी पर आई, जहां वोट गिनती में देरी हो रही थी, ट्रंप ने इसे 'धांधली' बताया। वेल्कर ने कहा कि कैलिफोर्निया में मेल-इन बैलट्स की वजह से देरी सामान्य है और कोई ठोस सबूत नहीं है। ट्रंप ने 2020 चुनाव को भी 'गंदा और धांधली वाला' बताया लेकिन सबूत पेश नहीं किए। वेल्कर के लगातार दबाव पर ट्रंप उत्तेजित हो गए। उन्होंने कहा कि आप बेईमान हैं, ठीक वैसे ही जैसे आपका नेटवर्क बेईमान है। या तो आप बेईमान हो या मूर्ख। आप उनके जाल में फंस रही हैं।

ट्रंप ने आगे कहा कि आप एकतरफा भ्रष्ट नेटवर्क हैं। 'मीट द प्रेस' भ्रष्ट है। एबीसी, सीबीएस, सीएनएन सब भ्रष्ट हैं। फिर उन्होंने माइक्रोफोन उतारकर जमीन पर फेंक दिया और कहा कि माफ कीजिए, चलिए यहीं समाप्त करते हैं। मेरा मन भर गया है। धन्यवाद डियर, आपका दिन अच्छा बीते।

वेल्कर ने इंटरव्यू जारी रखने की कोशिश की और याद दिलाया कि वे बारिश में विस्कॉन्सिन तक आई थीं।

पोर्ट, एयरपोर्ट से लेकर नेवल स्टेशन तक! भारत के लिए क्यों इतना अहम है ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट?

(जीएनएस)।

भारत सरकार हिंद महासागर में स्थित ग्रेट निकोबार द्वीप को एक बड़े आर्थिक और रणनीतिक हब के रूप में विकसित करने की तैयारी कर रही है। करीब 81,000 करोड़ रुपये की लागत वाले इस मेगा प्रोजेक्ट में पोर्ट, एयरपोर्ट, नेवल स्टेशन, टाउनशिप और पावर प्लांट का निर्माण किया जाएगा।

सरकार का कहना है कि यह सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि भारत की समुद्री ताकत, व्यापारिक क्षमता और क्षेत्रीय प्रभाव को बढ़ाने की दीर्घकालिक योजना का हिस्सा है। ऐसे में सवाल है कि आखिर सरकार का पूरा प्लान क्या है और ग्रेट निकोबार भारत के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जा रहा है?

ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट क्या है?

ग्रेट निकोबार अंडमान-निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी और रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण द्वीप है। सरकार यहां चार आपस में जुड़े प्रोजेक्ट विकसित करना चाहती है- इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट (कळळढ), ग्रीनफील्ड एयरफील्ड और नेवल एयर स्टेशन, आधुनिक टाउनशिप तथा पावर प्लांट। इन सभी परियोजनाओं पर कुल 81 हजार करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। उद्देश्य सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना नहीं, बल्कि इस द्वीप को एक विकसित आर्थिक और लॉजिस्टिक्स केंद्र में बदलना है।

सरकार का बड़ा प्लान क्या है?

सरकार की योजना ग्रेट निकोबार को हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के प्रमुख समुद्री गेटवे के रूप में विकसित करने की है। प्रस्तावित ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बड़े कंटेनर जहाजों को संभाल सकेगा, जबकि एयरफील्ड और नेवल स्टेशन नागरिक और रक्षा दोनों जरूरतों को पूरा करेंगे। टाउनशिप और पावर प्लांट स्थायी आबादी और आर्थिक गतिविधियों को समर्थन देंगे। सरकार का मानना है कि इससे द्वीपों में लंबे समय तक टिकाऊ विकास और भारत की मजबूत मौजूदगी सुनिश्चित होगी।

ग्रेट निकोबार की लोकेशन इतनी खास क्यों है?

ग्रेट निकोबार दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री व्यापार मार्गों के बेहद करीब स्थित है। हिंद महासागर से होकर एशिया, यूरोप और पश्चिम एशिया के बीच बड़ी मात्रा में व्यापारिक जहाज गुजरते हैं। यही वजह है कि इस क्षेत्र पर कई बड़ी शक्तियों की नजर रहती है। भारत के लिए यह लोकेशन समुद्री निगरानी, व्यापारिक कनेक्टिविटी और क्षेत्रीय प्रभाव बढ़ाने के लिहाज से बेहद अहम मानी जाती है।

भारत को क्या फायदा होगा?

अगर यह परियोजना सफल होती है तो भारत को आर्थिक और रणनीतिक दोनों स्तरों पर लाभ मिल सकता है। ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के जरिए भारत विदेशी बंदरगाहों पर निर्भरता कम कर सकता है। इससे शिपिंग और लॉजिस्टिक्स सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही एयरफील्ड और नेवल स्टेशन समुद्री सुरक्षा, आपदा राहत और निगरानी क्षमता को मजबूत करेंगे। सरकार का मानना है कि इससे हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की भूमिका और प्रभाव दोनों बढ़ेंगे।

आलोचना क्यों हो रही है और सरकार का जवाब क्या है?

कुछ पर्यावरण विशेषज्ञों और आलोचकों का कहना है कि यह प्रोजेक्ट पर्यावरण और स्थानीय इकोसिस्टम पर असर डाल सकता है। वहीं कुछ लोगों का आरोप है कि इसे रणनीतिक परियोजना बताकर कमर्शियल डेवलपमेंट को आगे बढ़ाया जा रहा है। हालांकि सरकार इन आरोपों को खारिज करती है। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार, रणनीति का मतलब सिर्फ सैन्य हित नहीं होता, बल्कि आर्थिक विकास, कनेक्टिविटी और राष्ट्रीय उपस्थिति भी उसका हिस्सा है। सरकार का कहना है कि ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट का लक्ष्य द्वीपों में दीर्घकालिक और संतुलित विकास सुनिश्चित करना है।

क्यों माना जा रहा है गेमचेंजर?

ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को भारत की समुद्री रणनीति का सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट माना जा रहा है। यह एक साथ व्यापार, कनेक्टिविटी, सुरक्षा और क्षेत्रीय प्रभाव को मजबूत करने की कोशिश है। ऐसे समय में जब हिंद महासागर वैश्विक प्रतिस्पर्धा का अहम केंद्र बनता जा रहा है, ग्रेट निकोबार भारत को आर्थिक और रणनीतिक दोनों मोर्चों पर नई ताकत दे सकता है। इसी वजह से इसे सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि भारत के भविष्य के समुद्री विजन का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है।

PRGI No.: UPHIN/25/A1697 Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By SUSHILA SHUKLA at Krishna Printiers, 271/31 Chakmaki Dugawa, Rajendranagar, Lucknow-226018, Uttar Pradesh.
and Published from 538 GHA/85 Pataurganj, Near Janki Prasad Dharmshala, Sitapur Road, Niralanagar, Lucknow-226020, Uttar Pradesh. Editor : ASHWANI KUMAR
Rage.Office: TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005 Gujarat,India. Phone : (O) 9016333307(M)9328333307,9825333307
Email : garvigujarat2007@gmail.com*garvigujarat2007@yahoo.com*Website : www.garvigujarat.co.in

कानपुर में अनवरगंज-मंधाना एलिवेटेड रेलवे ट्रैक का होगा निर्माण, पीएम मोदी करेंगे शिलान्यास

(जीएनएस)।

कानपुर। अनवरगंज-मंधना एलिवेटेड डबल रेलवे ट्रैक (15.51 किमी) निर्माण का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी करेंगे। इसी क्रम में अभी तीन जून को इज्जतनगर रेल मंडल (उत्तर पूर्व रेलवे) की डीआरएम वीणा सिन्हा ने मंधाना आकर वर्तमान स्थिति का जायजा भी ले चुकी हैं।

उधर, कार्य प्रारंभ होने से पहले कार्यदायी संस्था एलिवेटेड ट्रैक बनाने को सर्वे करा रही है। 1,115 करोड़ के इस मेगा प्रोजेक्ट का उद्देश्य शहर के घनी आबादी वाले इलाकों में 18 रेलवे क्रासिंग के कारण लगने वाले जाम से लोगों को मुक्ति दिलाना है।

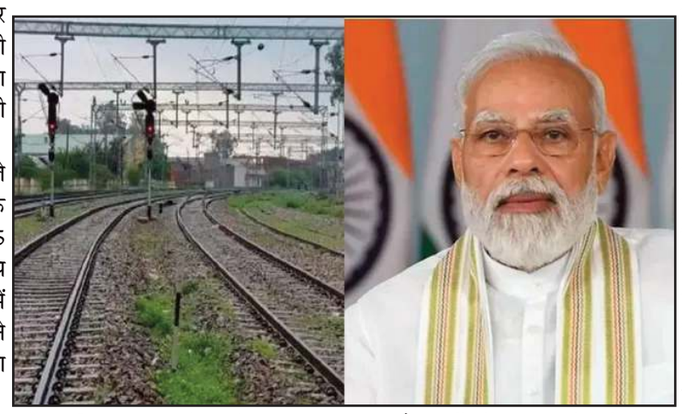

रेल सूत्रों के मुताबिक, एलिवेटेड डबल रेलवे ट्रैक निर्माण कार्य का प्रधानमंत्री से शिलान्यास कराने के लिए अधिकारियों ने पीएमओ को पत्राचार कर चुके हैं। कुछ समय में कार्यक्रम भी मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। रेलवे ट्रैक पर दो साल के लिए ब्लॉक लेने को रेल बोर्ड को पत्राचार पहले ही हो चुका है।

ट्रैक निर्माण में 300 से अधिक पेड़ बन रहे बाधा

अधिकारी दो महीने के अंतराल में ब्लॉक मिल जाने की उम्मीद भी कर रहे हैं। तब तक अन्य जरूरी कार्यों को पूरा किया जा रहा है। वर्तमान में यहां अनवरगंज-मंधना एलिवेटेड रेलवे ट्रैक के लिए कार्यदायी संस्था की तरफ से टोपोग्राफिकल सर्वे चल रहा है। इसमें पिलर मार्किंग के लिए देखा जा रहा है कि एलिवेटेड डबल ट्रैक को हवा में रोकने के लिए भारी-भरकम पिलर (खंभे) कहां-कहां खड़े किए जाएंगे, इसकी सटीक जगह तय की जा रही है। साथ ही बाधाओं की पहचान हो रही है।

पुराने ट्रैक के समानांतर मौजूद पेड़ों, बिजली के खंभों, सीवर लाइनों और अतिक्रमण को लिस्टेड किया जा रहा है। सर्वे के साथ ही स्टेशन डिजाइन पर भी काम चल रहा है। पूर्वोत्तर रेलवे की निर्माण विंग के इंजीनियरों का कहना है कि ट्रैक निर्माण में 300 से अधिक पेड़ बाधा बन रहे हैं। कई जगह अतिक्रमण भी है। विद्युत पोल, सीवर लाइन भी आड़े आ रहे हैं।

सीएसए ने रेलवे को हैंडओवर की जमीन

रावतपुर और कल्याणपुर स्टेशन को खत्म कर उनकी जगह केवल दलहन अनुसंधान केंद्र के पास "अटल स्टेशन" बनेगा। इसके लिए चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने रेलवे को 8874 वर्ग मीटर जमीन भी हैंडओवर करा दी है।

पीडब्ल्यूडी प्रांतीय खंड के सहायक अभियंता श्याम श्रीवास्तव ने बताया कि एलिवेटेड रेलवे ट्रैक के लिए 98.5 प्रतिशत जमीन रेलवे के पास पहले से उपलब्ध है। शेष डेढ़ प्रतिशत जमीन की और जरूरत है। जिसे पूरा करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र के संबंधित 70 भू-स्वामियों की जमीनों की रजिस्ट्री कराई जा रही है।

मेट्रो से स्काईवॉक से जुड़ेगा अटल स्टेशन

रेल विभाग के इंजीनियरिंग अनुभाग के अधिकारियों ने बताया कि अटल स्टेशन को स्काईवाक के जरिए पास के मेट्रो स्टेशन से सीधा जोड़ा जाएगा, जिससे यात्री बिना स्टेशन से बाहर निकले ट्रेन और मेट्रो बदल सकेंगे।

एलडीए व अग्निशमन विभाग के संयुक्त निरीक्षण में लखनऊ के होटलों में मिलीं कई खामियां

गोमती नगर के होटल नोवोटेल में पार्किंग की जगह बेकरी, लॉन्ड्री व स्टॉफ क्वॉर्टर बने थे। यह लापरवाही मिलने पर एलडीए ने होटल प्रबंधन को नोटिस जारी किया है। एलडीए व अग्निशमन विभाग की ज्वाइंट टीम ने सोमवार को शहर के 25 होटल, रेस्टोरेंट और क्लबों की जांच की।

(जीएनएस)।

लखनऊ , गोमती नगर के होटल नोवोटेल में पार्किंग की जगह बेकरी, लॉन्ड्री व स्टॉफ क्वॉर्टर बने थे। यह लापरवाही मिलने पर एलडीए ने होटल प्रबंधन को नोटिस जारी किया है। एलडीए व अग्निशमन विभाग की ज्वाइंट टीम ने सोमवार को शहर के 25 होटल, रेस्टोरेंट और क्लबों की जांच की। जिन जगहों पर कमियां मिलीं वहां अब एक्शन की तैयारी है।

जांच के आदेश दिए

एलडीए वीसी प्रथमेश कुमार ने बताया कि दिल्ली हादसे के बाद शहर में बहुमंजिला इमारतों में फायर सेफ्टी के इंतजामों की जांच के आदेश दिए गए हैं। प्रवर्तन और फायर डिपार्टमेंट की संयुक्त टीम गठित की गई है। सोमवार को अभियान चलाकर बहुमंजिला भवनों में संचालित होटलों व रेस्त्रां में जांच की गई। प्रवर्तन जोन-1 के जोनल अधिकारी देवांश त्रिवेदी व एफएसओ मामचन्द्र बड़गूजर के नेतृत्व में विराजखंड स्थित होटल नोवोटेल व होटल लीनेज समेत अन्य होटलों में जांच की। होटल नोवोटेल की ऊंचाई व सेटबैक मानकों के मुताबिक मिले लेकिन, स्वीकृत मैप में होटल के लोअर बेसमेंट में जिस जगह पार्किंग दिखाई गई थी, वहां बेकरी, लॉन्ड्री व स्टॉफ के लिए कमरे बने थे। होटल प्रबंधन को नोटिस जारी किया गया।

सेटबैक में अतिक्रमण

प्रवर्तन जोन-5 की जोनल अधिकारी वंदना पांडेय के नेतृत्व में टीम ने गुडंबा में कुर्सी रोड स्थित होटल एसएस ग्रैंड, आराधना इन, होटल जीआरपी समेत सात प्रतिष्ठानों में जांच की। होटल एसएस ग्रैंड में सेटबैक में अवैध निर्माण मिलने पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करायी गई। पांच प्रतिष्ठानों के स्वीकृत मैप तलब किए। प्रवर्तन जोन-2 के जोनल अधिकारी रवि नंदन सिंह ने टीम के साथ गोमती नगर विस्तार स्थित होटल-मर्करी व सुशांत गोल्फ सिटी स्थित होटल कम्फर्ट विस्ता एवं होटल सेंट्रम में जांच की।

होटल मंगलम पर होगी कार्रवाई

प्रवर्तन जोन-4 के जोनल अधिकारी माधवेश कुमार की अगुवाई में टीम ने हरदोई रोड स्थित होटल मंगलम पैलेस का निरीक्षण किया। जहां मानचित्र के विपरीत उपयोग व निर्माण कार्य मिलने पर कार्रवाई प्रचलित की जा रही है। इसी तरह आईआईएम रोड स्थित होटल एसडी पैलेस, होटल आरके ग्रैंड, नेशनल पैलेस व सीतापुर रोड स्थित होटल रेवांता में जांच की गई, इनसे स्वीकृत मानचित्र सम्बंधी दस्तावेज मांगे गये हैं।

पीएम मोदी ने अर्मेनिया के संसदीय चुनाव में प्रधानमंत्री निकोल को जीत की दी बधाई, सिविक कॉन्ट्रैक्ट पार्टी को मिले ज्यादा वोट

(जीएनएस)।

अर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिन्यान की पार्टी सिविक कॉन्ट्रैक्ट ने संसदीय चुनाव में शानदार जीत हासिल की है। भारत के पीएम मोदी ने पीएम निकोल को चुनाव में जीत की बधाई दी। अर्मेनिया में संसदीय चुनाव 7 जून को हुए थे। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जीत की बधाई देते हुए लिखा, 'संसदीय चुनाव में सिविल कॉन्ट्रैक्ट पार्टी की शानदार जीत पर निकोल पाशिन्यान को बधाई। नया जनादेश अर्मेनिया के लोगों के आपके नेतृत्व और विजन पर पक्के भरोसे और विश्वास को दिखाता है। मैं भारत और अर्मेनिया के बीच दोस्ती और सहयोग के गहरे और ऐतिहासिक संबंधों को और गहरा करने के लिए आपके साथ मिलकर काम करने का इंतजार कर रहा हूं।'

रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच अर्मेनिया में सिविक कॉन्ट्रैक्ट पार्टी की जीत ने सबका ध्यान खींचा है। यूरोपीय संघ और पश्चिमी देशों ने पीएम निकोल को इस जीत की बधाई दी। पिछले महीने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उन आर्थिक फायदों के बारे में बताया, जो अर्मेनिया को पश्चिमी देशों के साथ करीबी संबंध बनाने पर खोने पड़ सकते थे। रूसी राष्ट्रपति ने साफ तौर पर कहा कि यूक्रेन में संकट ईयू में शामिल होने की कोशिशों से शुरू हुआ था।

रूस अर्मेनिया को 177.50 डॉलर प्रति 1,000 क्यूबिक मीटर पर गैस सप्लाई करता है, जबकि यूरोपियन मार्केट की कीमतें, जैसा कि पुतिन ने अप्रैल में पाशिन्यान को बताया था, 600 डॉलर से ज्यादा हैं। चुनाव से पहले के दो हफ्तों में, रूस ने अर्मेनियाई फूलों, मिनरल वॉटर, कॉन्यैक, ताजी सब्जियों और फलों के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया था। चुनाव आयोग के अनुसार, शुरूआती नतीजों में पाशिन्यान की सिविल कॉन्ट्रैक्ट पार्टी 49.81 फीसदी वोटों के साथ आगे चल रही है, जबकि रूसी-अर्मेनियाई अरबपति सैमवेल करापेत्यान का स्ट्रॉन्ग अर्मेनिया अलायंस 23.29 फीसदी वोटों के साथ पीछे है।

पूर्व राष्ट्रपति रॉबर्ट कोचरियन का अर्मेनिया अलायंस लगभग 9.94 फीसदी वोटों के साथ तीसरे स्थान पर था, उसके बाद प्रॉस्पेरस अर्मेनिया पार्टी थी, जिसने 4 फीसदी वोटों के साथ चुनावी सीमा पार कर ली। कमीशन ने कहा कि 59.97 फीसदी वोट पड़े। सोमवार सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, पाशिन्यान ने कहा कि उनकी सिविल कॉन्ट्रैक्ट पार्टी जीत गई है, और इसे 'ऐतिहासिक जीत' बताया।

अपना मौसम उपग्रह विकसित करने को तैयार यूपी सरकार, सीएम योगी ने दिया हरसंभव सहयोग का आश्वासन

(जीएनएस)।

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मौसम पूर्वानुमान एवं अनुसंधान के क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में किए गए कार्यों के परिणाम स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। लखनऊ में क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र की स्थापना से उत्तर प्रदेश को विशेष लाभ मिलेगा। यह कदम विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक पहल है।

यूपी 11 प्रतिशत कृषि योग्य भूमि में प्रदेश देश का 21 प्रतिशत खाद्यान्न उत्पादन करता है। समय पर मौसम, बारिश, अतिवृष्टि, अनावृष्टि या ओलावृष्टि की जानकारी नहीं मिलेगी तो हम किसानों के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे।

क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना मौसम की और सटीक जानकारी प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सीएम ने सोमवार को केंद्रीय राज्यमंत्री डा. जितेंद्र सिंह संग बटन दबाकर क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश सरकार अपना यूपी-विशिष्ट उपग्रह चाहती है, जो मौसम संबंधी सटीक जानकारी देने में सक्षम हो।

यदि ऐसा कोई उपग्रह विकसित किया जाता है तो राज्य सरकार उसका पूरा समर्थन करेगी और सभी आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस संबंध में वह पहले भी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) से चर्चा कर चुके हैं।

योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र की स्थापना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए कहा कि आज केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में लखनऊ खुद को मेट्रोलाजिकल रीजनल सेंटर के रूप में स्थापित कर रहा है।

आपदा से तीन घंटे पहले मोबाइल पर अलर्ट

सीएम ने कहा कि 13 मई को आंधी-तूफान से प्रदेश के कुछ जिलों में जन-धन की काफी हानि हुई थी। बैठक में मैंने पूछा कि अर्ली वार्निंग सिस्टम क्यों काम नहीं कर रहा था? पता चला कि सिस्टम तो काम कर रहा है, लेकिन स्थानीय प्रशासन की सक्रियता का अभाव है।

फिर रात में पूरे प्रदेश के अधिकारियों के साथ वीडियो कान्फ्रेंसिंग में मैंने कहा कि जब अलर्ट मिल रहा है तो आपको भी स्थानीय स्तर पर लोगों व संस्थाओं को सतर्क करना चाहिए। इस बैठक के चौथे-पांचवें दिन भी आपदा आई, लेकिन तीन घंटे पहले सबके मोबाइल पर अलर्ट आना प्रारंभ हो गया।

मौसम के अलर्ट ने कीर्तन कर रहे श्रद्धालुओं को बचाया

सीएम ने सहारनपुर की घटना का जिक्र करते हुए बताया कि वहां शिवालिक पहाड़ी की तलहटी में मां शाकम्भरी देवी का मंदिर है। देहरादून व शिवालिक पहाड़ियों में भारी बरसात हुई। यहां बारिश होने से एकत्र होने वाला जल बाढ़ जैसा माहौल पैदा कर देता है। उस समय मंदिर में कीर्तन चल रहा था, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे, लेकिन मौसम विभाग ने समय से सही जानकारी दी तो सभी को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया गया, जिससे जनधन की व्यापक हानि रोकने में मदद मिली।

अर्ली वार्निंग सिस्टम का लाभ

मुख्यमंत्री ने कहा कि मीरजापुर, सोनभद्र, चंदौली आदि कई जिलों में आकाशीय बिजली का खतरा बहुत रहता है। हर वर्ष 100-150 लोगों की मौत होती थी। चार-पांच वर्ष पहले प्रयागराज से पटना के बीच आंधी व वज्रपात से एक ही दिन में 90 मौतें हुई थीं। इसमें यूपी के 30 व बिहार के 60 लोग शामिल थे।

इसके बाद एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, एमडीएमए, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की बैठक में मैंने पूछा कि आखिर इन मौतों को कौन रोकेगा? क्या इसे तकनीक से रोका नहीं जा सकता, तब विभाग ने बताया कि यह संभव है?

अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाने का परिणाम है कि इन जिलों में हर वर्ष होने वाली मौत के आंकड़े घटकर महज दर्जन भर रह गए। हालांकि, लोगों को भी ऐसे मौसम में लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए और मौसम के अलर्ट पर सतर्क रहना चाहिए।

मौसम चक्र में आया एक महीने का अंतर

सीएम योगी ने कहा कि मनुष्य ने जबसे बुद्धिमत्ता का उपयोग प्रारंभ किया होगा, उसके लिए सबसे पहले मौसम की जानकारी, आकाश में चमकती बिजली, बादलों से होने वाली वर्षा जैसी स्थितियां कौतूहल का विषय बनीं। ऋषि-मुनियों ने स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए पंचांग का निर्माण किया। आज भी ग्रह-नक्षत्रों के आधार पर की गई गणना मौसम की सटीक जानकारी का आधार बनती है।

लोक कहावतों, लोक परंपराओं में भी हम देखते थे कि अमुक चिड़िया की बोली या जानवरों का व्यवहार परिवर्तन मौसम की पूर्व जानकारी देने का माध्यम बनता था। उन्होंने कहा कि क्लाइमेट चेंज होने से मौसम चक्र में लगभग एक महीने का अंतर आया है। हमने स्वार्थ के लिए प्रकृति का दोहन किया है तो प्रकृति भी हमसे विमुख होती दिख रही है।

प्रदेश में 450 आटोमेटिक वेदर स्टेशन, ब्लाक स्तर पर 2000 ऑटोमेटिक रेनगेज स्थापित हुए हैं। इसके माध्यम से वर्षा की सटीक जानकारी किसानों को उपलब्ध कराते हैं। आजमगढ़, वाराणसी, अलीगढ़, झांसी, लखनऊ में एक्सबैंड डाप्लर वेदर राडार स्थापित किए जा रहे हैं।

कार्यक्रम में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक डॉ. मृत्युंजय महापात्र, क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र नई दिल्ली के प्रमुख डॉ. दुष्मंत रंजन पटनायक, लखनऊ मौसम केंद्र के प्रमुख डॉ. मनीष रमेश रानाल्कर आदि मौजूद रहे।

लखनऊ समेत 45 जिलों में आज से भीषण गर्मी

प्रदेश में रविवार को मौसम ने फिर करवट लिया। सोमवार को सूबे के 24 से अधिक जिलों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। मौसम विभाग का कहना है राज्य में अगले एक सप्ताह तक तापमान में लगातार वृद्धि हो सकती है। अगले पांच दिनों में लखनऊ समेत 45 से अधिक जिलों में दिन के पारे में तीन से पांच डिग्री तक बढ़ोत्तरी होने के पूवार्नुमान हैं। दोपहर 12 बजे के बाद बादलों की आवाजाही और तेज धूप की वजह से राजधानी में अधिकतम तापमान 40.3 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया, जबकि न्यूनतम पारा सामान्य से तीन डिग्री अधिक 29.7 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया।

वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के अनुसार, मंगलवार से 11 जून के दौरान प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में लू चलने का अलर्ट जारी किया गया है। सोमवार को 43.6 डिग्री सेल्सियस के साथ वाराणसी सबसे गर्म जिला रहा, जबकि 31.2 डिग्री सेल्सियस के साथ झांसी में सबसे गर्म रात रिकार्ड की गई।

यूपी में लौट रहे विलुप्त जीव! दुधवा में 117 साल बाद दिखा दुर्लभ सांप, सीएम योगी ने लिखी 'पाती'

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश वासियों के नाम 'योगी की पाती' लिखी है। इसमें उन्होंने जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए आम लोगों की भागीदारी पर जोर दिया है।

(जीएनएस)।

लखनऊ : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज प्रदेश के लोगों के नाम पत्र ' योगी की पाती ' लिखा है। उन्होंने इस पत्र में लोगों से कहा है कि जैव विविधता के संरक्षण का प्रयास जन भागीदारी बढ़ने पर ही सफल होगा। उन्होंने कहा है कि प्रकृति से विमुख होकर आधुनिक बनना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा है कि प्रकृति के बीच सिर्फ पर्यटक बनकर नहीं बल्कि जिज्ञासु विद्यार्थी बनकर जाएं। उन्होंने यूपी सरकार के प्रकृति संरक्षण के प्रयासों का जिक्र करते हुए बताया है कि, घास के मैदानों में अत्यंत दुर्लभ जर्डन्स बैबलर पक्षी वर्षों बाद दिखाई दिया। दुधवा टाइगर रिजर्व में पेंटेड कीलबैंक नाम के दुर्लभ सर्प की मौजूदगी 117 वर्ष बाद दर्ज की गई।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया वेबसाइट एक्स पर 'योगी की पाती' पोस्ट की है। उन्होंने इस पत्र में लिखा है- 'मेरे सम्मानित प्रदेश वासियो, सनातन संस्कृति में प्रकृति के प्रत्येक जीव को सृष्टि का अभिन्न अंग माना गया है। जैव विविधता के संरक्षण का प्रयास तभी सफल होगा, जब जन भागीदारी बढ़ेगी। '

अनुभवों पर ब्लॉग और आलेख लिखें

सीएम योगी ने लिखा है, 'मैं सभी से आग्रह करता हूं कि जब भी प्रकृति के बीच जाने का अवसर मिले, तो केवल पर्यटक बनकर नहीं, बल्कि जिज्ञासु विद्यार्थी की भांति उस स्थल को परखें। अपने अनुभवों को ब्लॉग और आलेखों के माध्यम से साझा करें। प्रकृति के प्रति जागरूकता और अपनापन ही हमारी जैव विविधता के सबसे बड़े संरक्षक हैं।'

उन्होंने लिखा है, 'वर्षा ऋतु में अलग-अलग कीट-पतंगों की आवाज, गर्मियों की रातों में जुगनुओं की चमक, भोर में गौरैयों की चहचहाहट और पेड़ों पर मैनाओं का कलरव, जो पहले दैनिक जीवन का हिस्सा थे, आज शहरों में लगभग दुर्लभ हो चुके हैं। इनकी लुप्तप्राय स्थिति चिंताजनक है और जीवन के लिए खतरे का सूचक।'

प्रकृति से विमुख होकर आधुनिक न बनें

मुख्यमंत्री ने लिखा है, 'आधुनिकता आवश्यक है, परंतु प्रकृति से विमुख होकर नहीं। जीव-जंतु प्रकृति के सौष्ठव का प्रतीक मात्र नहीं, अपितु स्वस्थ पर्यावरण का श्रृंगार हैं। प्रकृति का संतुलन भी छोटे-छोटे जीव-जंतुओं से बना रहता है। फसल उत्पादन से लेकर खाद्य श्रृंखला तक, प्रकृति के वृहत्तर चक्र में प्रत्येक जीव की महत्वपूर्ण भूमिका है।'

उन्होंने लिखा है, 'सनातन संस्कृति में प्रकृति के प्रत्येक जीव को सृष्टि का अभिन्न अंग माना गया है। त्रिलोक में अजेय माने जाने वाले दशानन का संहार करने वाली प्रभु श्रीराम की सेना में वानर से लेकर ऋक्ष, जटायु और नन्ही गिलहरी तक का योगदान था। यह मानव, प्रकृति तथा विभिन्न जीव-जंतुओं के परस्पर आश्रित रहने का परिचायक है।'

दुधवा में 117 साल बाद दिखा दुर्लभ सर्प

चिट्ठी में सीएम योगी ने लिखा है, 'नौ वर्ष पूर्व जब हमने कार्यभार संभाला था, तब पर्यावरण संरक्षण को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल किया गया था। वन्यजीव संरक्षण और पर्यावरण संवर्धन के सतत प्रयासों का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश में बाघों, तेंदुओं और राज्य पक्षी

यूपी में रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर खोलेंगे वस्त्रोद्योग और माटीकला क्षेत्र, सीएम योगी ने दिए निर्देश

(जीएनएस)।

लखनऊ। प्रदेश सरकार ने वस्त्रोद्योग और माटीकला क्षेत्र को रोजगार सृजन के बड़े माध्यम के रूप में विकसित करने की तैयारी तेज कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन दोनों क्षेत्रों के लिए ऐसी कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं, जो युवाओं, महिलाओं और पारंपरिक कारीगरों को कौशल विकास, आधुनिक तकनीक, वित्तीय सहायता और बाजार से जोड़ते हुए आत्मनिर्भरता की राह पर आगे बढ़ाए।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि प्रशिक्षण का उद्देश्य केवल प्रमाणपत्र देना नहीं, बल्कि रोजगार और स्वरोजगार के ठोस अवसर उपलब्ध कराना होना चाहिए। वस्त्रोद्योग व माटीकला क्षेत्र रोजगार व स्वरोजगार के नए अवसर खोलेंगे।

मुख्यमंत्री ने अपने आवास पांच कालिदास मार्ग में आयोजित समीक्षा बैठक में वस्त्र एवं परिधान क्षेत्र की वर्तमान जरूरतों और भविष्य की संभावनाओं के अनुरूप कौशल विकास व्यवस्था विकसित करने के निर्देश दिए।

कहा कि प्रदेश वस्त्रोद्योग के क्षेत्र में निवेश, उत्पादन और रोजगार के मामले में तेजी से अपनी पहचान मजबूत कर रहा है। ऐसे में उद्योगों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप प्रशिक्षित और दक्ष मानव संसाधन उपलब्ध कराना जरूरी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कौशल विकास कार्यक्रमों को उद्योगों की मांग के अनुरूप बनाया जाए ताकि प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले युवाओं को सीधे रोजगार के अवसर मिल सकें। उद्योगों की वास्तविक जरूरतों का आकलन कर प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को अधिक उपयोगी, आधुनिक और रोजगारपरक बनाया जाए।

उन्होंने कहा कि वस्त्र उद्योग में तकनीकी बदलाव तेजी से हो रहे हैं। आटोमेशन, आधुनिक मशीनरी और टेक्निकल टेक्सटाइल्स जैसे नए क्षेत्रों के विस्तार को देखते हुए प्रशिक्षण कार्यक्रमों को समयानुकूल बनाना जरूरी है।

माटीकला क्षेत्र की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। मिट्टी से बने उत्पाद पर्यावरण के अनुकूल होने के साथ-साथ हजारों परिवारों की आजीविका का आधार भी हैं।

उन्होंने माटीकला उत्पादों के उपयोग को बढ़ावा देने, कारीगरों को आधुनिक डिजाइन, सोलर चाक, उन्नत उपकरण और नई तकनीकों से जोड़ने पर जोर दिया। बैठक में बताया गया कि वर्ष 2019-20 से 2025-26 तक 1,331 इकाइयों की स्थापना की गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पारंपरिक उद्योगों को केवल संरक्षण देने की नहीं, बल्कि नवाचार, ब्रांडिंग, डिजिटलीकरण और आधुनिक बाजार से जोड़ने की आवश्यकता है। माटीकला उत्पादों को ई-कामर्स प्लेटफॉर्म, डिजाइन विकास और आधुनिक विपणन तंत्र से जोड़कर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में नई पहचान दिलाई जा सकती है।

मोदी सरकार के 12 सालः 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर, हर घर पहुंचा साफ पानी; संज्ञेय अपराधों में भी 6% की गिरावट

(जीएनएस)।

नई दिल्ली। देश में पिछले 12 वर्षों से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार 'सबका साथ, सबका विकास' के संकल्प के साथ विकसित भारत के लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के परिणाम दिखने लगे हैं। एक दशक में लगभग 25 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं, वहीं लोगों को महंगाई से राहत मिली है।

बहुआयामी गरीबी किसी व्यक्ति या परिवार की स्थिति को मापने का व्यापक तरीका है, जो गरीबी को केवल आय की कमी तक सीमित नहीं रखता। इसके अनुसार कोई व्यक्ति केवल धन की कमी से ही गरीब नहीं होता, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी जीवन स्तर (जैसे- स्वच्छ पानी, बिजली और आवास) के अभाव के कारण भी गरीबी में जीवन जीना पड़ता है।

ग्रामीण क्षेत्रों में 82 प्रतिशत घरों तक पहुंचा नल के स्वच्छ पानी

सरकार ने ग्रामीण इलाकों में पीने का साफ पानी पहुंचाने के लिए पूरा जोर लगा दिया। 19.35 करोड़ ग्रामीण घरों में से 81.87 प्रतिशत घरों में नल के स्वच्छ पानी पहुंचाया गया है। अगस्त 2019 में ग्रामीण क्षेत्रों में 3.23 करोड़ घरों नल का साफ पानी उपलब्ध था, वहीं मई 2026 तक 15.84 करोड़ घरों में नल का साफ पानी पहुंचा दी गई। हर घर जल अभियान के तहत 2.77 लाख गांवों में 100 प्रतिशत नल का पानी पहुंच चुका है।

भाजपा नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में जारी दस्तावेज में कहा गया है कि प्रत्येक ग्रामीण घरों में नल कनेक्शन के माध्यम से पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने के लिए 2019 में जल जीवन मिशन (जेजेएम) शुरू किया गया था।

ग्रामीण स्वच्छता का स्तर 2014 के 39 प्रतिशत से बढ़कर 100 प्रतिशत हो गया। 12.11 करोड़ से अधिक घरेलू शौचालय बनाए गए हैं। पीएम उज्ज्वला योजना के तहत 10.57 करोड़ से अधिक मुफ्त एलपीजी कनेक्शन दिए गए, जिससे महिलाओं का स्वास्थ्य बेहतर हुआ और घरों के अंदर होने वाला प्रदूषण कम हुआ।

58 करोड़ जन धन खातों से करोड़ों लोग बैंकिंग से जुड़े

सीतारमण वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 58 करोड़ से अधिक जन धन खातों ने करोड़ों भारतीयों को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से जोड़ा है। वित्त मंत्रालय के अनुसार, जन धन योजना के तहत कल्याणकारी योजनाओं, कम लागत वाले बीमा और पेंशन के लाभ सीधे लोगों तक पहुंच रहे हैं।

सीतारमण ने कहा, गरीबी के खिलाफ लड़ाई में भारत वैश्विक स्तर पर अलग पहचान बना रहा है। प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरूआत 28 अगस्त, 2014 को की गई थी। यह दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन पहल में से एक है। इस योजना के तहत 56 प्रतिशत खाताधारक महिलाएं हैं।

आयुष्मान भारत के तहत 43.93 करोड़ हेल्थ कार्ड जारी

गरीबों के स्वास्थ्य का भी सरकार ने पूरा ध्यान रखा है। आयुष्मान भारत योजना से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सस्ती स्वास्थ्य सेवा मिली है, जबकि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ने 81 करोड़ से अधिक लाभार्थियों के लिए मुफ्त अनाज सुनिश्चित किया है। प्राथमिक स्कूलों में लड़कियों के स्कूल छोड़ने की दर 2013-14 के 4.6 प्रतिशत से घटकर 2024-25 में 0.3 प्रतिशत रह गई।

संज्ञेय अपराधों में छह प्रतिशत की गिरावट

भारत में संज्ञेय अपराधों में छह प्रतिशत की गिरावट आई है। 2024 में 58.86 लाख संज्ञेय अपराध दर्ज किए गए, जो पिछले वर्ष की तुलना में छह प्रतिशत कम है। हत्या, दुष्कर्म जैसे अत्यंत गंभीर अपराधों को संज्ञेय अपराध कहते हैं। सोमवार को जारी एसबीआई रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर अपराध दर प्रति लाख जनसंख्या पर 448.3 से घटकर 418.9 हो गई है।

महिलाओं के खिलाफ अपराधों में 1.5 प्रतिशत की कमी आई है। 2023 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 4.48 लाख मामले आए थे जबकि 2024 में यह संख्या 4.41 लाख हो गई। हालांकि साइबर अपराध में 17 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो 2023 में 86,420 मामलों से बढ़कर एक लाख से अधिक हो गए।

रिपोर्ट के अनुसार सरकारी निवेश, बेहतर निगरानी और अधिक डिजिटलीकरण के कारण अपराधों के मामले घटे हैं। अनुमान है कि अपराध में एक प्रतिशत की कमी अल्पावधि में वास्तविक जीडीपी वृद्धि में लगभग 0.11 प्रतिशत की वृद्धि होती है, जबकि दीर्घकालिक प्रभाव बढ़कर 0.13 प्रतिशत हो जाता है।

सिर्फ 15 दिनों में 5 प्रतिष्ठित सम्मान पाकर वरिष्ठ समाजसेवी श्रीमती मंजू लोढ़ा का नया कीर्तिमान

मुंबई, समाजसेवा, महिला सशक्तिकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य जागरूकता और जनकल्याण के क्षेत्र में निरंतर कार्यरत वरिष्ठ समाजसेवी एवं साहित्यकार श्रीमती मंजू मंगल प्रभात लोढ़ा ने अपने प्रखर व्यक्तित्व और शानदार कृतित्व की बदौलत एक और उल्लेखनीय कीर्तिमान अपने नाम किया है। इसके अंतर्गत मात्र 15 दिनों के भीतर पाँच प्रतिष्ठित सम्मानों से सम्मानित होकर उन्होंने समाजसेवा के क्षेत्र में अपनी सक्रिय और प्रभावशाली भूमिका को एक बार फिर बखूबी सिद्ध किया है।

हाल ही में श्रीमती मंजू लोढ़ा को प्रतिष्ठित "बिलियनेयर फॉर पीस अवॉर्ड" से सम्मानित किया गया। साथ ही उन्हें बिलियनेयर फॉर पीस कॉन्क्लेव में पैनलिस्ट के रूप में आमंत्रित किया गया, जहाँ विश्व भर के प्रतिष्ठित नेता, विचारक और परिवर्तनकारी व्यक्तित्व शांति, मानवता और न्याय जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा के लिए एकत्रित हुए। इस अवसर पर उन्होंने डॉ. हुजैफा खोराकीवाला के प्रति आभार व्यक्त किया। इसके बाद उन्हें प्रतिष्ठित पद्मश्री महेंद्र कपूर अवॉर्ड्स समारोह में उनके अतुलनीय योगदान के लिए 'महाराष्ट्र आइकॉन अवॉर्ड' से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उनके सामाजिक कार्यों, महिला सशक्तिकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य जागरूकता एवं जनहित के लिए किये जा रहे निरंतर प्रयासों की सराहना के रूप में प्रदान किया गया। इस अवसर पर उन्होंने श्री दत्तात्रय माने का विशेष आभार व्यक्त किया। साथ ही उन्होंने स्वर्गीय महेंद्र कपूर के परिवारजनों रोहन कपूर, नीरजा कपूर एवं सिद्धांत कपूर के प्रति भी अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। इसी क्रम में टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा भी श्रीमती मंजू लोढ़ा को परोपकार, सामाजिक प्रभाव, स्वास्थ्य जागरूकता, महिला सशक्तिकरण और सामुदायिक सेवा के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित किया गया। यह सम्मान प्रसिद्ध अभिनेता रणदीप हुड्डा द्वारा प्रदान किया गया, जो उनके समाज के प्रति समर्पण और सेवा भावना का एक और प्रमाण है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय अधिवेशन में श्रीमती मंजू लोढ़ा को 'अमर शहीद मंगल पांडे अवॉर्ड ऑफ एक्सीलेंस-2026' से सम्मानित किया गया। यह कार्यक्रम श्री राकेश पांडे, श्री मुकेश पांडे एवं श्री हरेश मेहता के सहयोग से आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में प्रसिद्ध अभिनेता राजपाल यादव तथा वरिष्ठ चिंतक एवं समाजसेवी पवन त्रिपाठी उपस्थित रहे। यह सम्मान उन्हें समाज कल्याण, पर्यावरण जागरूकता एवं राष्ट्र निर्माण के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान किया गया। इनके अलावा हाल ही में उन्हें उनके परोपकारी कार्यों और समाजसेवा के लिए 'मुंबई अचीवर्स अवॉर्ड 2026' से भी सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें आभा सिंह द्वारा प्रदान किया गया, जो समाज एवं समुदाय के उत्थान के लिए उनके निरंतर योगदान के उपलक्ष्य में प्रदान किया गया। इस अवसर पर उन्होंने मीना बाफना, हसमुख बाफना एवं वरुण बाफना का विशेष आभार व्यक्त किया। श्रीमती मंजू लोढ़ा ने कहा कि प्रत्येक सम्मान उनके लिए समाज के प्रति अपनी ज़िम्मेदारियों को और अधिक निष्ठा एवं समर्पण के साथ निभाने की प्रेरणा देता है। उनका मानना है कि समाजसेवा केवल एक कार्य नहीं, बल्कि जीवन का उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि वे आगे भी शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण संरक्षण और जनकल्याण के क्षेत्रों में निरंतर कार्य करती रहेंगी। लगातार प्राप्त हो रहे ये सम्मान उनके अथक परिश्रम, सेवा भावना और समाज के प्रति समर्पण का प्रमाण हैं। श्रीमती मंजू लोढ़ा आज न केवल महाराष्ट्र बल्कि पूरे देश में समाजसेवा, महिला सशक्तिकरण और मानवीय मूल्यों की सशक्त प्रेरणा एवं उदाहरण बनकर उभरी हैं।

समाज सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए विभिन्न संस्थाओं द्वारा आयोजित समारोहों में श्रीमती मंजू लोढ़ा के सम्मान एवं प्रमुख प्रतिभागिता के विविध दृश्य।

छत्तीसगढ़ में कंगना रनौतः सीएम साय के साथ देखी 'भारत भाग्य विधाता', नर्सों की वीरता को किया सलाम

फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' 26/11 मुंबई आतंकी हमले के दौरान कामा अस्पताल की नर्सों के साहस और समर्पण को समर्पित है.

(जीएनएस)।

रायपुरः भाजपा सांसद और बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत अपनी फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' की विशेष स्क्रीनिंग के लिए रायपुर पहुंचीं. शहर के जोरा स्थित मॉल में आयोजित स्क्रीनिंग में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, सांसद बृजमोहन अग्रवाल सहित मंत्री और विधायक भी विशेष स्क्रीनिंग शामिल हुए. फिल्म देखने के बाद मुख्यमंत्री ने कंगना के अभिनय की सराहना की और कहा कि यह फिल्म 26/11 मुंबई आतंकी हमले के दौरान कामा अस्पताल की नर्सों के साहस और समर्पण को श्रद्धांजलि है. वहीं एयरपोर्ट पर मीडिया से चर्चा करते हुए कंगना रनौत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की जमकर प्रशंसा की और उन्हें वैश्विक नेतृत्व का प्रतीक बताया.

फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' स्क्रीनिंग

भाजपा सांसद एवं अभिनेत्री कंगना रनौत अपनी नई फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' की स्पेशल स्क्रीनिंग सीएम विष्णु देव साय के साथ देखी. इस दौरान कंगना रनौत और मुख्यमंत्री साय ने फिल्म के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की. रायपुर एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत में कंगना रनौत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की खुलकर प्रशंसा की. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को लगातार जनसमर्थन मिल रहा है और

वे विश्व के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक बनकर उभर रहे हैं. कंगना ने कहा कि पूरी दुनिया नेतृत्व के लिए उनकी ओर देख रही है और भारत को विश्वगुरु के रूप में स्थापित होते हुए देखना गर्व की बात है.

पीएम मोदी के नेतृत्व की तारीफ कंगना रनौत ने की

10 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले प्रधानमंत्री बनने के अवसर पर कंगना रनौत ने इसे देश के लिए गौरव का क्षण बताया. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को देशभर में जो सम्मान और लोकप्रियता मिल रही है, वह उनकी कार्यशैली और नेतृत्व क्षमता का परिणाम है, दुनिया उन्हें वैश्विक मार्गदर्शन के प्रतीक के रूप में देख रही है.

फिल्म भारत भाग्य विधाता' देखने की अपील की

अपनी फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' को लेकर कंगना रनौत ने लोगों से इसे देखने की अपील की. उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि सेवा, समर्पण और साहस की प्रेरणादायक कहानी है, जिसे हर भारतीय को देखना चाहिए.

नर्सों की वर्दी पर भी रखी राय

भारतीय अस्पतालों में नर्सों की वर्दी पर ब्रिटिश प्रभाव और उसे भारतीय स्वरूप देने के सवाल पर कंगना ने कहा कि यह उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है, लेकिन नर्सों के लिए सबसे बेहतर वही होगा जो वे स्वयं पसंद करें. उन्होंने कहा कि इस विषय पर निर्णय लेने का अधिकार और समझ सबसे अधिक नर्सों के पास ही है.

सीएम साय ने की फिल्म और कंगना के अभिनय की सराहना

फिल्म देखने के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कंगना रनौत का धन्यवाद करते हुए कहा कि उन्होंने अपनी फिल्म की स्क्रीनिंग के लिए छत्तीसगढ़ को चुना, यह राज्य के लिए गौरव की बात है. मुख्यमंत्री ने कहा कि कंगना ने फिल्म में नर्स की भूमिका को बेहद प्रभावशाली ढंग से निभाया है.

26/11 के दौरान नर्सों के काम और उनके साहस को समर्पित है फिल्म

मुख्यमंत्री साय ने बताया कि 'भारत भाग्य विधाता' 26/11 मुंबई आतंकी हमले के दौरान कामा अस्पताल की नर्सों द्वारा दिखाई गई बहादुरी और सेवा भावना पर आधारित है. आतंकियों के हमले के बीच नर्सों ने जिस साहस के साथ घायलों की सेवा की, उसी प्रेरक कहानी को फिल्म के माध्यम से दर्शाया गया है. रायपुर में फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' की स्क्रीनिंग केवल एक सिनेमाई आयोजन नहीं रही, बल्कि 26/11 के दौरान मानवता, सेवा और साहस की मिसाल पेश करने वाले स्वास्थ्यकर्मियों को श्रद्धांजलि देने का अवसर भी बनी. वहीं कंगना रनौत ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व और भारत की वैश्विक भूमिका को लेकर अपने विचार रखकर राजनीतिक संदेश भी दिया.

रजिस्ट्री कार्यालयों को बनाएं पारदर्शिता और जनसुविधा का आदर्श मॉडल : योगी

पासपोर्ट सेवा केंद्रों की तर्ज पर विकसित होंगे रजिस्ट्री कार्यालय, नागरिक सुविधाएं होंगी बेहतर, मूल्यांकन व्यवस्था से रुकेगी स्टाम्प शुल्क चोरी, घटेंगे विवाद

(जीएनएस)।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को स्टाम्प एवं पंजीयन विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, निवेश गतिविधियों और शहरीकरण की आवश्यकताओं के अनुरूप विभाग को अधिक पारदर्शी, तकनीक आधारित, उत्तरदायी और जनसुविधा केंद्रित बनाया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि रजिस्ट्री कार्यालय आमजन के प्रत्यक्ष संपर्क वाले कार्यालय हैं, इसलिए वहां की व्यवस्थाएं आधुनिक, व्यवस्थित और नागरिक केंद्रित होनी चाहिए। उन्होंने उप निबंधक कार्यालयों को चरणबद्ध ढंग से पासपोर्ट सेवा केंद्रों की तर्ज पर विकसित करने की आवश्यकता बताई।

बैठक में बताया गया कि प्रदेश के रजिस्ट्री कार्यालयों में प्रतिवर्ष लगभग 2.4 करोड़ लोगों का प्रत्यक्ष संपर्क होता है। इसे देखते हुए हेल्प

डेस्क, टोकन एवं क्यू मैनेजमेंट सिस्टम, आधुनिक प्रतीक्षालय, महिला एवं शिशु कक्ष, डिजिटल सुविधाएं तथा अन्य नागरिक सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी व्यवस्था विकसित की जाए जिससे नागरिकों को अनावश्यक प्रतीक्षा और असुविधा का सामना न करना पड़े।

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्टाम्प एवं पंजीयन विभाग राज्य की राजस्व व्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार है। बैठक में बताया गया कि वर्ष 2016-17 में विभाग की सकल आय 11,613.84 करोड़ रुपये थी, जो वर्ष 2025-26 में बढ़कर 32,598.49 करोड़ रुपये हो गई है। इसी अवधि में पंजीकृत लेखपत्रों की संख्या 28.25 लाख से बढ़कर 49.34 लाख से अधिक हो गई। मुख्यमंत्री ने इस प्रगति को आगे बढ़ाते हुए राजस्व वृद्धि के साथ सेवा गुणवत्ता और नागरिक संतुष्टि को भी प्राथमिकता देने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि डिजिटल गवर्नेंस विभागीय सुधारों का प्रमुख आधार बनना चाहिए। संपत्ति एवं विवाह पंजीकरण में आधार प्रमाणीकरण, बायोमेट्रिक और आईरिस आधारित सत्यापन, ऑनलाइन दस्तावेज सत्यापन तथा खतौनी आधारित डिजिटल जांच जैसी व्यवस्थाओं को और सुदृढ़ किया जाए। पेपरलेस रजिस्ट्रेशन प्रणाली, अभिलेखों के डिजिटाइजेशन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित कार्यप्रणाली तथा जियो-टैगिंग व्यवस्था को तेजी से लागू करने की दिशा में प्रभावी कार्यवाही की जाए। उन्होंने कहा कि तकनीक के माध्यम से पारदर्शिता बढ़ाने, विवाद कम करने और राजस्व अपवंचन रोकने में मदद मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि संपत्तियों के मूल्यांकन में एकरूपता और पारदर्शिता लाने के लिए मानकीकृत मूल्यांकन व्यवस्था विकसित की जानी चाहिए। इससे बाजार आधारित मूल्यांकन सुनिश्चित होगा तथा मूल्यांकन संबंधी विवादों में कमी आएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश तेजी से निवेश और औद्योगिक विकास का केंद्र बन रहा है। ऐसे में विधिक व्यवस्थाओं को भी वर्तमान आर्थिक और व्यावसायिक आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि व्यवस्थाओं में स्पष्टता होने से निवेशकों का विश्वास बढ़ता है, अनावश्यक विवाद और मुकदमेबाजी कम होती है तथा कारोबार करने की सुगमता को बल मिलता है।

बैठक में कॉरपोरेट पुनर्गठन, विलय, विभाजन, समामेलन, अधिग्रहण, सीमित दायित्व भागीदारी (एलएलपी), शेयरधारिता में परिवर्तन, आवासीय सहकारी समितियों तथा रेरा के अंतर्गत विक्रय करारों से जुड़े विषयों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इन क्षेत्रों में स्पष्ट और व्यावहारिक स्टाम्प शुल्क व्यवस्था विकसित की जानी चाहिए। उन्होंने निर्देश दिए कि विभिन्न राज्यों की सर्वोत्तम व्यवस्थाओं का अध्ययन करते हुए ऐसा विधिक ढांचा तैयार किया जाए जिससे निवेश को प्रोत्साहन मिले, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मजबूत हो, विवादों में कमी आए और राज्य के राजस्व हित भी सुरक्षित रहें।

लखनऊ में आठवें वेतन आयोग की टीम सेवा संघों के साथ करेगी बैठक, वित्तीय स्थिति से अवगत कराएंगे अधिकारी

आठवें केंद्रीय वेतन आयोग की टीम 22 और 23 जून को लखनऊ में सेवा संघों और वित्त विभाग के अधिकारियों से मिलेगी। अधिकारी

(जीएनएस)।

लखनऊ। आठवें केंद्रीय वेतन आयोग की टीम 22 व 23 जून को लखनऊ प्रवास पर रहेगी। टीम के सदस्य यहां पर सेवा संघों, संस्थानों व संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर उनकी मांगें सुनेंगे। आयोग की टीम वित्त विभाग के अधिकारियों के साथ भी बैठक करेगी।

आयोग की टीम के आगमन का कार्यक्रम तय होने पर वित्त विभाग के छह अधिकारियों को विषय विशेष की जानकारी देने तथा उनके रहने व खाने-पीने की व्यवस्था की जिम्मेदारी दी गई है। विशेष सचिव वित्त नील रतन कुमार को नोडल अधिकारी नामित किया गया है।

इनके अलावा विशेष सचिव आलोक दीक्षित, वीके सिंह, पुष्पराज व अनुराग गुप्ता के साथ ही अपर निदेशक सिद्धार्थ श्रीवास्तव को अहम जिम्मेदारियां दी गई हैं। ये अधिकारी आयोग को बताएंगे कि छठवें और सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों को लागू करने से राज्य की वित्तीय स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा था।

इसके अलावा पेंशन व सेवानिवृत्ति के बाद दिए जाने अन्य लाभों तथा समस्त भत्तों व सुविधाओं की जानकारी भी देंगे।बैठकों में राज्य स्तरीय अखिल भारतीय संघों के प्रतिनिधि भी आमंत्रित किए जाएंगे।

योगी सरकार की दिव्यांग पेंशन योजना बनी सहारा, लाखों लाभार्थियों को मिल रही आर्थिक मदद

सीएम योगी के मार्गदर्शन में लाखों दिव्यांगजनों के जीवन में पेंशन योजना से सकारात्मक बदलाव आएं हैं. जिससे लाभार्थियों को आर्थिक सुरक्षा के साथ जीवन जीने का अवसर मिला है.

(जीएनएस)।

उत्तर प्रदेश के लाखों दिव्यांगजनों के जीवन में दिव्यांग भरण-पोषण अनुदान/पेंशन योजना से सकारात्मक बदलाव आएं हैं. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में संचालित इस योजना से लाभार्थियों को आर्थिक सुरक्षा और आत्मसम्मान के साथ जीवन जीने का अवसर मिला है. लाभार्थियों का कहना है कि समय पर पेंशन मिलने से दवा, भोजन और अन्य जरूरी खर्चों को पूरा करने में मदद मिल रही है. कई परिवारों के लिए यह पेंशन जीवनयापन का सहारा बन गई है. लाभार्थियों ने मुख्यमंत्री योगी की सराहना करते हुए कहा कि सरकार की यह पहल उनके जीवन को आसान और सुरक्षित बना रही है.

पेंशन से घर की आर्थिक स्थिति को मिली मजबूती

बाराबंकी की रहने वाली आशा और उनके पति हरिलाल ने बताया कि पेंशन मिलने से उनके घर की आर्थिक स्थिति को मजबूती मिली है. उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद देते हुए कहा कि सरकार की इस सहायता से परिवार को बड़ी राहत मिली है. हरिलाल ने बताया कि उनकी पत्नी आशा एक हाथ से दिव्यांग हैं, जबकि वह स्वयं सांस की गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं. स्वास्थ्य संबंधी

समस्याओं के कारण वह नियमित रूप से काम नहीं कर पाते हैं. ऐसे में दिव्यांग पेंशन उनके परिवार के लिए जीवनरेखा का काम कर रही है.

योगी सरकार से पेंशन राशि बढ़ाने की मांग

हरिलाल ने बताया कि समय पर पेंशन मिलने से दवा और अन्य आवश्यक जरूरतों का खर्च निकल जाता है, जिससे उन्हें आर्थिक सहायता के लिए इधर-उधर भटकना नहीं पड़ता है. उन्होंने बताया कि उनकी चार बेटियां हैं और सीमित आय के बीच परिवार का भरण-पोषण करना किसी चुनौती से कम नहीं है, लेकिन पेंशन मिलने से काफी सहारा मिला है.

पेंशन योजना दिव्यांगजनों के लिए साबित हो रही उपयोगी

इसी तरह लखनऊ के गोसाईगंज निवासी 35 वर्षीय कौशल को भी पिछले 5-6 साल से पेंशन का लाभ मिल रहा है. कौशल ने बताया कि योगी सरकार आने के बाद उन्हें दिव्यांग पेंशन का लाभ मिलना शुरू हुआ है. उन्हें प्रत्येक तीन महीने पर 3000 रुपये की पेंशन मिलती है, जिससे उनके जीवन-यापन में काफी मदद मिलती है. कौशल बाएं पैर से दिव्यांग हैं.